सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 151, नई दिल्ली । रविवार, 11 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा ।

03 जमानतियों की राजनीति से होगा देश का बेडापार
06 अब विकसित भारत की डगर
08 बांग्लादेश के बड़े नेता ने खोल दी प्रदर्शन की पोल

उपराज्यपाल दिल्ली का सम्बोधन "अधिकारी बिना डर और दबाव के काम करें, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता" के कारण ही परिवहन विभाग में आला अधिकारी नियम और क़ानून के बाहर काम कर रहे है क्या?

संजय बाटला

नई दिल्ली। उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा दिल्ली सरकार में कार्यरत उच्च अधिकारियों को दिल्ली सरकार से बिना डर और दबाव लिए काम करने के लिए संबोधित कर यह कहा है कि वह उनके साथ है या नियम/ कानून को ताक पर रखकर अपनी इच्छा के काम करने के लिए उन्हें साथ देने की बात कही है, बड़ा सवाल ? दिल्ली परिवहन विभाग में आयुक्त एवम विशेष परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश, दिशा निर्देश और अन्य कार्यों के प्रति लगातार मुख्य सचिव और उपराज्यपाल दिल्ली को शिकायतो के बाद भी कार्यवाही नहीं होना तो किसी और दिशा में दिए जा रहे समर्थन को दर्शा रहा हैं। 1. दिल्ली परिवहन में महिला सुरक्षा प्रणाली जान बुझकर शुरू ना होने देना। 2. जनहित का नाम लेकर जनता को ही परेशानियां में डालना, 3. बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को फायदा पहुंचाना, 4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के गैजेट नोटिफिकेशन से विपरीत कार्य करना, 5. तकनीकी अधिकारियों को गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति देना और 6. गैर तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी पदों पर आसीन करना, क्या दिल्ली सरकार का डर और दबाव है बड़ा सवाल ? दिल्ली सरकार में आला पदों पर आसीन अधिकारी अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहे है तो उनको समर्थन की नही अपितु उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है और यह ही दायित्व माननीय उपराज्यपाल दिल्ली का बनता है की वह उनके खिलाफ जांच के आदेश जारी करे।

पंजाब में NHAI प्रोजेक्टों पर ग्रहण: केंद्र ने पंजाब सरकार को दी चेतावनी-प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रखें

पंजाब में हाल ही में एनएचएआई के ठेकेदारों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई थीं। अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा है। इसमें पंजाब सरकार को चेतावनी दी गई है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक रखें नहीं तो परियोजनाएं कैंसिल कर दी जाएंगी।

नई दिल्ली। पंजाब में एनएचएआई की कई परियोजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को पत्र लिख इसकी चेतावनी दी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरती है तो एनएचएआई की आठ और परियोजनाओं को रद्द कर दिया जाएगा।

गडकरी ने यह पत्र दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर ठेकेदारों के साथ हुई हिंसक घटनाओं के बाद लिखा है। पत्र में कहा गया है कि एनएचएआई पंजाब में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे सहित कई एनएच कॉरिडोर का निर्माण रहा है। हाल ही में घटनाओं के बाद उन्होंने अथॉरिटी के अधिकारियों, ठेकेदारों और उनके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को भी हाल करने के लिए कहा है।

वहीं इस मामले में पंजाब के आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री की निगरानी में है। हमने इस पर एसआईटी गठित की है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानून-व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसी दो घटनाएं हुई हैं और अगर एनएचएआई को जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा मुहैया कराएंगे।

शहर से कई शहरों के लिए चलेंगी डीलक्स बसें, परिवहन अधिकारियों ने 15 बसों का प्रस्ताव भेजा

परिवहन विशेष न्यूज

पहले चरण में डीलक्स एसी बसों को धार्मिक स्थलों वाले शहरों में चलाने की योजना है। कानपुर के झकरकटी और सिग्नेर ग्रीन्स सिटी बस अड्डे से इनका संचालन किया जाएगा।

कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) निजी बस सेवा को टक्कर देने की तैयारी में है। परिवहन मुख्यालय में कई डीलक्स एसी बसें आने वाली हैं, जिनका कई शहरों में संचालन किया जाएगा। कानपुर को एक दर्जन से अधिक बसें मिलने की उम्मीद है। यहां के अधिकारियों ने 15 बसों का प्रस्ताव भेजा है। इन्हें लखनऊ होकर अयोध्या धाम, गोरखपुर, प्रयागराज होकर वाराणसी, बांदा होते हुए चित्रकूट, दिल्ली और एनसीआर के शहरों में चलाने की प्लानिंग है।

एक डीलक्स बस दिन तो दूसरी रात में संचालित हो सकती है। इन बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी। आरामदायक सीटों के साथ ही पूरी तरह से वातानुकूलित रहेंगी। शहर में निजी बस संचालकों की ओर से दिल्ली, हरिद्वार, जयपुर, अजमेर, वाराणसी, गोरखपुर, भोपाल, इंदौर समेत अन्य रूट पर बसें संचालित हो रही हैं। इनमें ज्यादातर एसी और नॉन एसी स्लीपर बसें हैं।

इस सेवा के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से टिकट की बुकिंग होती है। इनकी सर्विस को देखते हुए काफी संख्या में यात्री इनसे सफर करने को वरियता दे रहे हैं। ट्रेनों में लंबी वेटिंग की वजह से भी लोग इनमें यात्रा कर रहे हैं। इन बसों की बेहतर सर्विस का असर रोडवेज की बसों के संचालन पर पड़ रहा है। त्योहार को छोड़कर कई रूटों पर सीमित सवारियां मिल रही हैं। इस समस्या को देखते हुए डीलक्स एसी बसें संचालित करने की तैयारी है।

धार्मिक स्थलों वाले शहरों में चलेंगी

पहले चरण में डीलक्स एसी बसों को धार्मिक स्थलों वाले शहरों में चलाने की योजना है। कानपुर के झकरकटी और सिग्नेर ग्रीन्स सिटी बस अड्डे से इनका संचालन किया जाएगा। इन बसों का किराया अभी चल रहीं जनरथ बसों से अधिक रहेगा। इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर पर होगा।

अनुबंध पर भी हो सकती संचालित

परिवहन अधिकारियों के मुताबिक कई डीलक्स बसें खरीदी जाएंगी, जबकि कछ बसों को अनुबंध के आधार पर चलाया जा सकता है। इनका किराया भी निर्धारित रहेगा। परिवहन अधिकारी बसों की लगातार मॉनीटरिंग करेंगे।

शहर में नए साल से कुछ रूटों पर डीलक्स एसी बसें संचालित हो सकती हैं। मुख्यालय स्तर पर प्रस्ताव मांगे गए थे, जिसमें कुछ रूटों की रिपोर्ट भेजी गई है। यह बसें काफी सुविधाजनक रहेंगी। -अनिक कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीएसआरटीसी

एक महीने तक विंडसर पैलेस पर एक तरफा ही चलेगा ट्रैफिक, एनडीएमसी ने जारी की एडवाइजरी

एनडीएमसी ने लोगों की सुविधा के मद्देनजर यातायात सलाह जारी की है। अशोका रोड पर एनडीएमसी द्वारा सीवर बैरल मरम्मत काम के कारण यातायात डायवर्जन प्रभावी रहेगा। इसके चलते एक महीने तक विंडसर पैलेस पर ट्रैफिक एक तरफा ही चलेगा। एनडीएमसी ने लोगों को कस्तूरबा गांधी मार्ग का वैकल्पिक तौर पर उपयोग करने की सलाह दी है।

नई दिल्ली। ली मैरीडियन होटल के सामने गोल चौराहे विडंसर पैलेस पर आंशिक तौर पर यातायात बंद रहेगा। एनडीएमसी ने यहां पर मौजूद सीवर बैरल की मरम्मत के लिए यह निर्णय लिया है। एनडीएमसी ने इसकी एडवाइजरी जारी कर दी है।

28 जून को धंस गई थी सड़क

नागरिकों को सलाह दी है कि वैक्लपिक तौर पर कस्तूरबा गांधी मार्ग का उपयोग करें। एनडीएमसी के अनुसार अशोक रोड से विडसर पैलेस होते हुए जसवंत सिंह चैंबरी तक का मार्ग खुला रहेगा। उल्लेखनीय है कि विंडसर पैलेस के पास अशोका रोड पर 28 जून को सड़क धंस गई थी।

इसकी वजह से 15 दिन तक यहां पर एनडीएमसी ने मरम्मत का काम किया था, लेकिन पूरी सफलता न मिलने के बाद अब एनडीएमसी ने यहां से गुजरने वाली सीवर लाइन के बैरल की मरम्मत का निर्णय लिया है।

एनडीएमसी के अनुसार 12 अगस्त से 10 सितंबर तक गोल चक्कर पर आंशिक तौर पर यातायात चलेगा। विंडसर पैलेस गोल चौराहा बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है। इंडिया गेट से आने वाला यातायात पटेल चौक से लेकर संसद मार्ग और कनॉट प्लेस जाने के लिए उपयोग किया जाता है।

नजफगढ़ फिरनी रोड पर यातायात प्रभावित

ढांसा स्टैंड और बहादुरगढ़ स्टैंड पर जलभराव के कारण नजफगढ़ फिरनी रोड पर यातायात प्रभावित है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट कर लोगों से इस मार्ग से जाने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा आनंद पर्वत पर सड़क पर गड्ढों के कारण न्यू रोहतक रोड पर दोनों तरफ यातायात प्रभावित है।

पेट्रोल पंप पर भी कटेगा चालान: वाहन चालक भूल से भी न करें ये गलती, नहीं तो लगेगी 10 हजार रुपये की चपत

परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कंपनी को 15 दिन के अंदर कम से कम 25 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए सिस्टम तैयार कर देने को कहा गया है। उसके बाद कुछ दिन में 100 पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी जांच का सिस्टम लग जाएगा।

नई दिल्ली। बिना पीयूसी के पेट्रोल पंपों पर वाहन में पेट्रोल भराने पहुंचे तो 10000 का चालान कटना तय है। दिल्ली सरकार ने 100 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए कैमरे लगाने व सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए निजी कंपनी नवगति टेक को टेंडर आवंटित कर दिया है। कंपनी को 15 दिन के अंदर अपनी सेवाएं शुरू करनी है। कंपनी को पांच साल के लिए ठेका दिया गया है।

परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि कंपनी को 15 दिन के अंदर कम से कम 25 पेट्रोल पंपों पर पीयूसी जांच के लिए सिस्टम तैयार कर देने को कहा गया है। उसके बाद कुछ दिन में 100 पेट्रोल पंपों पर पीयूसीसी जांच का सिस्टम लग जाएगा। इसकी अनुमानित लागत छह करोड़ रुपये है। योजना के तहत पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों में वैध पीयूसीसी नहीं होने पर प्रदूषण जांच के लिए कुछ घंटों की मोहलत भी दी जाएगी और इस अवधि में पीयूसी नहीं बनवाने पर स्वतः ही 10000 रुपये का ई-चालान कट जाएगा और इसकी सूचना वाहन मालिक को मोबाइल पर भेज दी जाएगी।

बता दें कि दिल्ली सरकार के दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) की यह योजना है। योजना के तहत अभी फिलहाल 100 पेट्रोल पंपों पर यह व्यवस्था शुरू की गई, बाद में 400 पेट्रोल पंपों पर की जाएगी।

एनएच के साथ लगतीं सड़कों की मरम्मत के लिए केंद्र से मांगे 52 करोड़

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले को उठा चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी गडकरी से यह मामला उठाया है।

शिमला। एनएच के साथ लगतीं जिलों की सड़कों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग ने केंद्र से पैसा जारी करने के लिए रिमाइंडर भेजा है। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 52 करोड़ रुपये मांगे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले को उठा चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी गडकरी से यह मामला उठाया है। बीते साल बरसात में आई प्राकृतिक आपदा के चलते हिमाचल में कई नेशनल हाईवे बंद हो गए थे। ऐसे में जिला सड़कों से वाहनों की आवाजाही हुई।

उस दौरान केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे के दौरान केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। हिमाचल में आपदा के चलते 17 पुल ढह गए। अकेले लोक निर्माण विभाग को 2913.05 करोड़ का नुकसान हुआ है। अन्य विभागों की अपेक्षा यह बहुत ज्यादा है। इन सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि एनएच बंद होने से वाहनों की आवाजाही जिला सड़कं और संपर्क मार्ग सहारा बने थे। केंद्र सरकार ने सड़कों को ठीक करने के लिए पैसा देने की हामी भरी थी, अभी यह पैसा नहीं मिला है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

रविवार विशेष -सूर्य देव

समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ सम्पूर्ण संसार के कर्ताधर्ता है बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जिनके दर्शन के बिना किसी के भी दिन का आरंभ नहीं होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य का उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। सूर्यदेव को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यानी जिसके गर्भ में ही सुनहरे रंग की आभा है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान का विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है।

❁ सूर्य- पिता, स्वास्थ्य, यश सम्मान, प्रशासनिक नौकरियां व व्यापार के कारक ग्रह है। कुंडली में इनके शुभ होने से इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है।

❁ उदयगामी सूर्य को प्रणाम करना प्रगति की निशानी है। इसीलिए सुबह- सुबह स्नान करके उगते सूर्य को देखना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

❁ सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ₹ॐ घृणि सूर्याय नमः₹ या फिर ₹ॐ सूर्याय नमः₹ कहते हुए जल अर्पित करें।

❁ सूर्य को दिए जाने वाले जल में केवल लाल, पीले पुष्प मिला सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी प्रकार की सामग्री जल में नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि इससे जल की पवित्रता भंग होती है।

❁ अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिम्ब एक बिन्दु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा।

❁ सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे।

❁ सूर्य देव की सात प्रदक्षिणा करें व हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सूर्यनारायण के समक्ष आप इन मंत्रों का जाप भी कर सकते है-:

1- ॐ सूर्याय नमः।
2- ॐ मित्राय नमः।
3- ॐ रवये नमः।
4- ॐ भानवे नमः।
5- ॐ खगाय नमः।
6- ॐ पूष्णे नमः।
7- ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
8- ॐ मारीचाय नमः।
9- ॐ आदित्याय नमः।
10- ॐ सावित्रे नमः।
11- ॐ अर्काय नमः।
12- ॐ भास्कराय नमः।।

रक्षाबंधन विशेष, 19 अगस्त 2024 सोमवार

भाई बहन के स्नेह का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन इस बार 19 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर काफी अच्छे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है- :

ग्रह- गोचर योग-:

* इस बार दो बड़े ग्रह सूर्य व शनि अपनी स्वयं की राशि में रहेगें। सूर्य अपनी सिंह राशि में रहेंगे तो शनि कुंभ राशि में, ग्रह अपनी स्वयं की राशि में अक्सर शुभ फल ही प्रदान करते हैं। साथ में सूर्य व बुध दोनों का सिंह राशि में होने से बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा, ज्योतिष शास्त्र में यह योग सुख, समृद्धि व व्यापारिक क्षेत्र में प्रगतिदायक माना जाता है।

योग-:

* इस दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक शुभ योग सुबह 8:11 तक रहेगा और इस दिन शोभन योग भी संपूर्ण दिन व्याप्त रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है।

नक्षत्र-:

* इस दिन श्रवण व धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बनेगा। श्रवण नक्षत्र सुबह 8:11 तक रहेगा, उसके उपरांत घनिष्ठा नक्षत्र संपूर्ण दिन व्याप्त रहेगा। ये दोनों नक्षत्र ही शुभ माने गए हैं।

भद्रा:काल-:

* सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 01:35 तक भद्रा काल का समय रहेगा, अतः भद्रा काल में होलिका दहन/ रक्षाबंधन आदि पर्व मनाना वर्जित माना गया है। अतः भद्राकाल समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा।

चौघड़िया-:

* दोपहर 02: 02 से रात्रि 08:18 तक क्रमशः चर, लाभ, अमृत, व चर के अच्छे चौघड़िये रहेंगे। अतः इस समय के दौरान रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाना शुभ रहेगा।

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त-:

* दोपहर 02:05 से रात्रि 08:18 तक का समय राखी बांधने के लिए सबसे उपयुक्त समय रहेगा।।

मानसून में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यह चाय किसी चमत्कार से कम नहीं है, फायदे जानकर होश उड़ जाएंगे

स्वस्थ शरीर के लिए न जाने हम सभी क्या-क्या उपाय करते हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी से लेकर ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए करी पत्ते की चाय का सेवन बेहद लाभकारी है। वैसे तो करी पत्ते का इस्तेमाल खाने में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इसकी आपने कभी चाय नहीं पी होगी। आइए जानते हैं करी पत्ते की चाय पीने से क्या लाभ होते हैं।

हर घर में करी पत्ते का पेड़ जरुर होता है या फिर बाजार में आसानी करी पत्ता मिल जाता है। करी पत्ते को खाने की सुगंध और स्वाद बढ़ाने का इस्तेमाल किया जाता है। करी पत्ता बालों के लिए सबसे हेल्थी माना जाना है। करी पत्ते में कई पोषक तत्व पाए जाते है। लेकिन क्या आप ने कभी करी पत्ते की चाय बनाकर पी है। अगर नहीं, तो आइए इससे होने वाले लाभों के बारे में जानते हैं।

करी पत्ता पोषक तत्वों का भंडार है

करी पत्ते में कॉपर, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन-सी, मैग्नीशियम और जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं कि करी पत्ते की चाय पीने से क्या लाभ मिलते हैं।

इम्यूनिटी होगी मजबूत

करी पत्ते में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये सभी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। करी पत्ते की चाय पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है और आप खुद को कई मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं।

तनाव होगा दूर

वैसे तो करी पत्तों में कई पोषक तत्व पाए जाते है। अगर आप करी पत्ते की चाय का सेवन करते हैं दिमाग शांत हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं।

पाचन तंत्र में होगा सुधार

करी पत्ते में कई गुण मौजूद होते हैं, जो पाचन-तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं। करी पत्ते की चाय पीने से पाचन संबंधी समस्याओं को कम किया जा सकता है।

ब्लड शुगर होगा कंट्रोल

अगर आप करी के पत्तों की चाय पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा। करी पत्ते की चाय का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है।

मतली की समस्या दूर होती है

करी पत्ते मतली की समस्या का इलाज करते हैं। इन पत्तों के सेवन से मतली और उल्टी की समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं। अगर आप करी पत्ते की चाय पीतें हैं तो मतली की समस्या दूर हो जाएगी।

थायराइड की है समस्या तो जरूर करें धनिया का सेवन

मिताली जैन

धनिया में क्वेरसेटिन और विटामिन सी जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप धनिया का सेवन करते हैं तो इससे थायराइड कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं, जिससे थायराइड फ़ंक्शन में सुधार हो सकता है।

धनिया का इस्तेमाल हम सभी अपनी किचन में जरूर करते हैं। कभी धनिया के बीज को खाना पकाते हुए शामिल करते हैं तो कभी हरा धनिया की मदद से अपने खाने को गार्निश करते हैं। धनिया में कई तरह के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं और इसलिए जब इसे आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो इससे आपकी सेहत को लाभ मिलता है। हालांकि, अगर आपको थायराइड की समस्या है, तो धनिया आपक लिए विशेष रूप से लाभदायी है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि थायराइड रोगियों के लिए धनिया किस प्रकार फायदेमंद साबित हो सकता है-

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

धनिया में क्वेरसेटिन और विटामिन सी जैसे एंटी-ऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए जब आप धनिया का सेवन करते हैं तो इससे थायराइड कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाने में मदद करते हैं, जिससे थायराइड फ़ंक्शन में सुधार हो सकता है।

होते हैं डिटॉक्सीफाइंग गुण

धनिया को अपने डिटॉक्सीफाइंग गुणों के लिए जाना जाता है। ऐसे में जब आप धनिया का सेवन करते हैं तो इससे शरीर से मर्करी जैसे हैवी मेटल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। ये हैवी मेटल्स थायराइड फ़ंक्शन में बाधा डाल सकती हैं, इसलिए जब शरीर में इन मेटल्स की उपस्थिति कम होती है तो थायराइड हेल्थ इंप्रूव हो सकती है।

कोलेस्ट्रॉल को करे कंट्रोल

थायराइड को अक्सर बहुत सी बीमारियों से जोड़ा जाता है। कुछ मामलों में, थायराइड के कारण नई बीमारियां विकसित होने लगती हैं। थायराइड का मुख्य कारण कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि है। धनिया के बीज कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे थायराइड हार्मोन को भी कंट्रोल रखने में मदद मिलती है।

वजन को मैनेज करने में सहायक

धनिया मेटाबॉलिज्म और पाचन में सुधार करने में मददगार है, जिससे वजन प्रबंधन में मदद मिलती है। यह हाइपोथायरायड रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। हाइपोथायरायड मरीजों को अक्सर बढ़ते वजन की शिकायत होती है, लेकिन धनिया की मदद से आप अपने वजन को बैलेंस कर सकते हैं।

ब्रेस्ट मिल्क पंप का इस्तेमाल महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

अनन्या मिश्रा

बहुत महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि क्या ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग सही होता है या नहीं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग से जुड़ी कई बातें बताने जा रहे हैं।

आजकल ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग यानी स्तन का दूध निकालना काफी ज्यादा चलन में है। खासकर यह प्रक्रिया वह महिलाएं ज्यादा अपनाती हैं, जो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाती हैं या फिर वह नौकरी करती हैं। ऐसे में वह अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग का इस्तेमाल करती हैं।

हालांकि बहुत महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि क्या ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग सही होता है या नहीं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग से जुड़ी कई बातें बताने जा रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग का इस्तेमाल करती हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

जानिए ब्रेस्ट मिल्क पंप करने के फायदे

बता दें कि ब्रेस्ट मिल्क पंप करने से महिलाओं को लचीलापन मिलता है। ऐसे में वह किसी भी समय बच्चे को स्तनपान करवा सकती हैं।

जब बच्चा समय से पहले जन्म लेता है, तो उस दौरान बच्चे को सीधे तौर पर स्तनपान नहीं करवा सकते हैं। इसलिए इस दौरान बच्चे को पंप किया हुआ दूध देना चाहिए।

ब्रेस्ट मिल्क पंप करने के नुकसान

एक्सपर्ट के अनुसार, ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग के कई नुकसान होते हैं। अगर आप घर पर रहती हैं, तो आपको बच्चे को स्तनपान ही करवाना चाहिए, क्योंकि यह नेचुरल और सही तरीका होता है। लेकिन अगर आप नौकरी करती हैं और घर से बाहर रहती हैं, तो आप स्तनपान के लिए ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं।

ब्रेस्ट मिल्क पंप से दूध निकालने का प्रोसेस अलग होती है, इस प्रक्रिया को सही तरीके से न करने से महिलाओं के ब्रेस्ट गांठ बन सकती है।

इस प्रक्रिया के अधिक इस्तेमाल से दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है।

ब्रेस्ट मिल्क पंप के इस्तेमाल से टिश्यू और निप्पल डैमेज हो सकते हैं।

यह दूध पिलाने पर बच्चे को पोषण तत्व नहीं मिल पाते हैं।

ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसको स्टोर करने पर इसमें बैक्टीरिया होने का खतरा पैदा हो सकता है।

कैसे करें ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग

बता दें कि ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग तब करना चाहिए, जब यह काफी जरूरी हो।

इस प्रक्रिया को करने से पहले बोतल और ब्रेस्ट दोनों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए।

दिल्ली मेट्रो में फिर मारपीट, दो युवकों की लड़ाई और गाली-गलौज का वीडियो हो रहा वायरल

दिल्ली मेट्रो शहर की जीवन रेखा बन गई है और इसे आवागमन के सबसे सुविधाजनक साधनों में से एक माना जाता है। हालांकि इन दिनों दिल्ली मेट्रो अजीबोगरीब कारणों से चर्चा में रहता है इसमें ज्यादातर मामले यात्रियों के असामान्य व्यवहार से जुड़े हैं। मेट्रो से बेतरतीब लड़ाई-झगड़े सार्वजनिक रूप से प्यार जताना डांस रील और अजीबोगरीब ड्रेसिंग के कई वीडियो सामने जाते रहते हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में कभी डांस करते युवक-युवतियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो कभी गलत हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) मेट्रो में ऐसे गलत आचरण करने वाले यात्रियों का जुर्माना करने का दावा भी करता है। मेट्रो पुलिस ने कुछ मामलों में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की है। फिर भी मेट्रो में ऐसी घटनाएं थम नहीं रही हैं।

दो यात्रियों में हुई मारपीट

इसी क्रम में मेट्रो में मारपीट का एक वीडियो दो दिन से तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक्स पर इतने ज्यादा लोगों ने शेयर किया है शनिवार शाम को दिल्ली मेट्रो ट्रेंड कर रही थी।

वीडियो में दो युवा एक दूसरे मारपीट और गाली-गलौज करते दिख रहे हैं। उस वक्त मेट्रो में ज्यादा भीड़ भी नहीं दिख रही है। फिर भी दो युवा मारपीट करते दिख रहे हैं।

रोजाना लाखों यात्री करते हैं सफर

मेट्रो में प्रतिदिन 60 लाख से अधिक यात्राएं यात्री करते हैं। इस वजह से व्यस्त समय में मेट्रो में काफी भीड़ होती है। इस वजह से हाल के दिनों में मेट्रो में मारपीट की घटनाएं भी बढ़ी है। इस वजह से मेट्रो में मारपीट के कई पुराने वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

1600 से ज्यादा लोगों पर हुई कार्रवाई

डीएमआरसी ने मेट्रो में उपद्रव मचाने के लिए 1600 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की है। डीएमआरसी ने अप्रैल से जून के दौरान मेट्रो परिसर में उपद्रव मचाने और रील बनाने के लिए 1600 से ज्यादा लोगों पर एक्शन लिया है। हाल ही में डीएमआरसी ने यह जानकारी दी है।

वित्त मंत्री आतिशी ने एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी की बैठक में 427 करोड़ की लागत के नए कोर्ट काम्प्लेक्स बनाने को दी मंज़ूरी

सुषमा रानी

नई दिल्ली दिल्ली में ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस दिशा में केजरीवाल सरकार राउज एवेन्यू में नया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स बनाने की तैयारी में है। एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी की बैठक में वित्त मंत्री आतिशी ने 427 करोड़ रुपये लागत के इस परियोजना को मंजूरी दी।

इस विषय में साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, जल्द और सुलभ न्याय हर भारतीय का मूल अधिकार है और यह तभी संभव है जब न्यायालयों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि, वर्तमान में, देश भर में न्यायाधीशों और अदालतों पर लंबित मुकदमों का बहुत बोझ है, जिससे मामलों के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है। ऐसे में राजधानी में पर्याप्त न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता है। इस दिशा में राउज एवेन्यू में नयें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम्प्लेक्स में 55 कोर्ट रूम्स बनाए जाएँगे जो दिल्ली में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा।

आतिशी ने कहा कि, इस दिशा में ये प्रोजेक्ट दिल्ली के ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके पूरा होने के बाद न्यायिक मामलों को तेज़ी से निपटाने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि, इन तीनों प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ भी तैयार की जायेंगी।

राउज एवेन्यू में प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की विशेषताएँ

-2 ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

-ब्लॉक A 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित 11 मंज़िला होगा। इसमें 55 कोर्ट रूम बनाए जाएँगे।

-ब्लॉक-B 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर सहित 17 मंज़िला होगा। इसमें 815 लॉयर चैम्बर्स बनाये जाएँगे।

-स्काईवॉक से जोड़े जाएँगे दोनों बिल्डिंग ब्लॉक

-लाइब्रेरी, बेसमेंट पार्किंग, कॉन्फ्रेंस रूम, जुडिसियल ऑफिस सहित तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया कोर्ट काम्प्लेक्स।

इस प्रोजेक्ट में जज़ों, वकीलों और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बेहतर सार्वजनिक सुविधाएँ भी तैयार की जाएगी।

वित्त मंत्री आतिशी ने प्रोजैक्ट्स को लेकर विभागों को आदेश दिए है कि एक विस्तृत टाइमलाइन तैयार कर तेज़ी से इन प्रोजैक्ट्स को पूरा करने की दिशा में काम किया जाए।

जमानतियों की राजनीति से होगा देश का बेडापार

परिहवन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। शुक्रवार को दिल्ली के आम आदमी पार्टी के शूरवीर मनीष सिसौसिदिया जमानत पर छूटने वाले 10 नेताओ की फेहरिस्त में शामिल हो गए है। अब तक इनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, लालू प्रसाद यादव, अभी जमानत पर है। इनके अलावा तेजस्वी यादव, हेमंत सौरेन, डीके शिवकुमार, संजय राउत, अनिल देशमुख, संजय सिंह, चन्द्र बाबू नायडू, और अब एक नाम मनीष सिसौदिया का और जुड गया है। जमानत पर बाहर आकर राजनीति करने वाले सिसौदिया पहले नेता नही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देश की 7 बडी पार्टियों के 10 बडे नेता अभी जमानत पर है, और राजनीति कर रहे है। गौरतलब है कि एक को छोडकर सभी नेता विपक्ष के हैं, और इन सभी पर 2014 के बाद ही मुकदमा दायर हुआ है। बता दे कि जमानत पर बाहर आकर राजनीति करने वाले एक नेता पार्टी प्रमुख, दो नेता मुख्यमंत्री और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। इन नेताओ की राजनीति कुंडली इस प्रकार है:- (1) सोनिया गांधी और राहुल गांधी:- कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में जमानत पर है। दोनों मां-बेटे पर नेशनल हेराल्ड की संपति में हेर फेर का आरोप है। दोनों ही नेताओ को साल-2015 में दिल्ली की निचली अदालत ने जमानत दी थी। तब से दोनो बाहर है। बता दें कि हेराल्ड केस का साल 2012 में खुलासा हुआ था। इस केस में सोनिया गांधी और राहुल समेत कांग्रेस के 8 नेता ईडी के रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड केस में अब तक 830 करोड रूपये की संपति अटैच की है। [2] पी चिदंबरम:- देश के पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम भी जमानत पर बाहर है। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में आरोपी है। और उन्हें 2019 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 2 महीने बाद सुप्रीमकोर्ट ने चिदंबरम को जमानत दे दी। चिदंबरम अभी राज्य सभा के सांसद है। और कांग्रेस के लिए पीछे से रणनीति तैयार करते है। (3) लालू प्रसाद यादव:- चारा घोटाले में सजायाफ्ता और लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोपी लालू प्रसाद यादव अभी जमानत पर है। उन्हे फिलहाल स्वास्थ्य के बेस पर कोर्ट से जमानत मिली हुई है। हाल ही में सीबीआई उनके खिलाफ कोर्ट गई थी। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की दलील सुनने से इंकार कर दिया। (4) तेजस्वी यादव:- लैंड फॉर स्कैम केस में आरोपी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी जमानत पर है। उन्हें अक्टूबर-2023 में जमानत मिली थी। (5) हेमंत सोरेन:- झारखंड के मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन भी जमानत पर है। सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। उन्हें ईडी ने जनवरी-2024 में गिरफ्तार किया था। जून 2024 में हेमंत को झारखंड हाईकोर्ट ने भी जमानत को बरकरार रखा था। (6) डीके शिव कुमार:- कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी अभी जमानत पर बाहर है। कुमार पर मनी लांड्रिंग का आरोप है। उन्हें 2019 सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन की हिरासत के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जांच अभी भी जारी है। (7) संजय राउत:- शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी जमानत पर बाहर है। राउत पर पात्रा चाल पुनर्विकास मामले में मनी लांड्रिंग का आरोप है। उन्हें अगस्त-2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के 103 दिन बाद मुंबई हाईकोर्ट ने राउत को जमानत दे दी। (8) अनिल देशमुख:- महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जमानत पर है। देशमुख पर 100 करोड रूपये की कथित वसूली का मामला है उन्हे दिसंबर-2022 से मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। (9) संजय सिंह:- आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जमानत पर ही है। सिंह पर मनी लांड्रिंग का आरोप है। और उन्हें अक्टूबर-2023 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीमकोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। (10) चन्द्रबाबू नायडू :- आन्ध्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू भी जमानत पर है। उन पर कौशल विकास मामले में धांधली का आरोप है। नायडू को जनवरी 2024 में नियमित जमानत मिली थी। उनकी पार्टी इस मुद्दे के सहारे चुनाव में गई। वर्तमान में नायडू केंद्र की एनडीए सरकार में किंग मेकर की

> *आपकी जानकारी के लिए बता दे कि देश की 7 बडी पार्टियों के 10 बडे नेता अभी जमानत पर है, और राजनीति कर रहे है। गौरतलब है कि एक को छोडकर सभी नेता विपक्ष के हैं, और इन सभी पर 2014 के बाद ही मुकदमा दायर हुआ है। बता दे कि जमानत पर बाहर आकर राजनीति करने वाले एक नेता पार्टी प्रमुख, दो नेता मुख्यमंत्री और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर है।*

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंगबाजी से हो सकता है बड़ा नुकसान, दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा कि चूंकि 15 अगस्त के आसपास पतंग उड़ाने वालों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग उड़ाने पर उसकी डोर बिजली के तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पेंटोग्राफ यूनिट में फंसने की आशंका रहती है। इससे पतंग उड़ानेवाले के लिए जानलेवा हो सकता है और इससे मेट्रो परिचालन बाधित हो सकती है।

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंगबाजी की घटना को लेकर दिल्ली मेट्रो ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने कहा कि चूंकि 15 अगस्त के आसपास पतंग उड़ाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग उड़ाने पर उसकी डोर बिजली के तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पेंटोग्राफ यूनिट में फंसने की आशंका रहती है।

दिल्ली मेट्रो ने एक बयान में कहा कि एलिवेटेड मेट्रो लाइनों की ऐसी घटनाओं से न केवल ओ.एच.ई या पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंच सकता है बल्कि इससे बिजली ट्रिप होकर मेट्रो सेवाएं बाधित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही, धातु के मांझे के साथ पतंग उड़ाने वालों के लिए भी यह जानलेवा साबित हो सकता है।

डेडिकेटेड टीम के द्वारा निगरानी

डीएमआरसी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामान्य तौर पर इन दिनों डीएमआरसी पतंगबाजी की आशंका वाले स्टेशनों के पास डेडिकेटेड टीमों के द्वारा निगरानी बनाए रखती है। ये टीमें इन दिनों पतंग की डोर दिखने पर सावधानी बरतने, ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह देने के अलावा पतंग की डोर को तुरंत हटाने का काम करती हैं।

डीएमआरसी ने जारी की सलाह

दिल्ली मेट्रो ने कहा कि इस बचाव संबंधी व्यवस्था के अलावा दिल्ली मेट्रो आमलोगों से अपील भी करती है कि वे अपनी स्वयं की सुरक्षा एवं मेट्रो के निर्बाधित परिचालन के लिए बिजली के तारों के पास पंगबाजी न करें । ऐसा करना उनकी जान को भी जोखिम में डाल सकता हैं और मेट्रो सेवाएं भी बांधित हो सकती है।

मेट्रो यात्रियों की सुरक्षा और निर्बाध मेट्रो सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो जनता को मेट्रो लाइनों से दूर खुली जगहों पर सुरक्षित रूप से, पतंग उड़ाने का आनंद लेने की सलाह देती है।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किला पर फुल ड्रेस रिहर्सल, परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस इस बार भी सुरक्षा बंदोबस्त कुछ बदलाव किए हैं। रक्षा और गृह मंत्रालय की निगरानी में सेना, पारा मिलिट्री और सभी केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस करीब दो माह से सुरक्षा तैयारी में जुटी हुई थी।

कड़ी चौकसी का ही नतीजा है कि बीते दिनों स्पेशल सेल ने राजधानी से आईएसआईएस के एक आतंकी को दबोच लिया। हो सकता है उसकी मंशा स्वतंत्रता दिवस समारोह वाले दिन अथवा पहले राजधानी को दहलाने की हो। दहशतगर्दों के किसी भी तरह के नापाक मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है।

सुरक्षा के बेहद खास बंदोबस्त

सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से लेकर लालकिला तक सुरक्षा के बेहद खास बंदोबस्त किए गए हैं कि ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। लालकिला व प्रधानमंत्री के रूट समेत पूरी दिल्ली में जगह-जगह पुलिस व पारा मिलिट्री की तैनाती की गई है। 13 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। इसको लेकर कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा। इससे सभी एजेंसियां सुरक्षा तैयारियां परखेगी। अगर कहीं खामियां का पता चलेगा तो उसे दुरुस्त किया जाएगा।

बंदरों को भगाने के लिए लंगूर का बंदोबस्त

पुलिस अधिकारी के मुताबिक पिछले साल फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान डमी प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान एक बंदर के आ जाने से सुरक्षा कर्मियों के होश उड़ गए थे। इससे सभी एजेंसियों के सुरक्षा तैयारियों की जांच की गई थी। उसे देखते हुए बंदरों को भगाने के लिए इस बार लंगूर का भी बंदोबस्त किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहले हर साल एनसीसी के करीब 1000 बच्चे भाग लेते थे। इस बार एनसीसी के अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के बच्चे भी समारोह में भाग लेंगे। यानी करीब 2,500 बच्चे भाग लेंगे। इस बार 24 अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर देश वासियों के सामने मिसाल पेश करने वाले लोगों को समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया गया है।

छतों पर एंट्री एयरक्राफ्ट व एयर डिफेंस गन लगाए गए

हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा व्यवस्था में सेना के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी, एयरफोर्स व देवी समेत दिल्ली पुलिस को लगाया गया है। आसमान से कोई लालकिला व उसके आसपास ड्रोन, बैलून, पारा ग्लाइडर व अन्य तरीके से हमला न कर दे, इसके लिए लालकिला, आईएसबीटी, गीता कॉलोनी फ्लाई ओवर, सिविक सेंटर (निगम मुख्यालय) आदि 300 से अधिक ऊंची इमारतों की छतों पर एंट्री एयरक्राफ्ट व एयर डिफेंस गन लगाए गए हैं। इन हथियारों के जरिए हवाई हमले से मिनटों में निपटा जा सकेगा।

सभी 15 जिले को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश

सेना के हेलीकाप्टर से लाल किले के आसपास सुरक्षा का जायजा लिया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने सभी 15 जिले की पुलिस को पूरी तरह अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख आयोजन स्थल लाल किला सहित आसपास के इलाके मध्य दिल्ली व नई दिल्ली में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लालकिला के आसपास की सभी ऊंची इमारतों पर सोमवार से सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे।

10 अगस्त को ना-इन्साफी दिवस मनाया गया

दलित मुसलमानों की आरक्षण की मांग हुई तेज़

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: अगस्त को "ना-इन्साफी दिवस" के तौर पर मनाते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने जंतर-मंतर पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज़ गुलाम सरवर ने किया।

धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए हाफिज सरवर ने कहा कि 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन नेहरू सरकार ने मात्र एक अध्यादेश द्वारा संविधान की धारा 341 पर धार्मिक प्रतिबन्ध लगाकर भारत के पसमांदों (दलित मुस्लिमो) को अनु० जा० की सूची से निष्कासित कर दिया। सरकार का ये एक्शन मूलतः गैर संविधानिक, और भेद-भाव से ग्रसित था लेकिन सरकारी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए ऐसा किया गया जिसका प्रभाव ये पड़ा कि पसमांदा समाज शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर रेस में सबसे पीछे छूट गया और आज अत्याचार का शिकार है। मोर्चा के उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम हवारी ने कहा कि दलित मुस्लिम के इस इशू पर सारी पॉलिटिकल पार्टियां अंधी, बहरी और गुंगी बनी हुई है। 1994 से इस एकल इशू पर चली आ रही तहरीक पर अल्पसंख्यक आयोग, सच्चर कमिटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग, गुगली कमिटी रिपोर्ट यहाँ तक कि वाजपेयी जी की संविधान समीक्षा आयोग ने भी अपनी सहमति दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इस मामले को केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर फेंक देती है और सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार पर।

करवाने इत्तेहाद के संयोजक जीशान हैदर मलिक ने कहा कि 2019 में अयोध्या मसले के हल के समय मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट से ये 4 अर्ज किया था कि बड़े भाई (हिन्दु समाज) को अयोध्या की विवादित जमीन देकर उन्हें ₹सम्मानः दे दिया जाए और छोटे भाई (मुस्लिम समाज) को धारा 341 में शामिल कर उन्हें ₹वरदानः दे दिया जाए। उस समय 1949-50 से चले आ रहे ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में फाइनल स्टेज पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े भाई को ₹सम्मानः तो दे दिया लेकिन छोटा भाई ₹वरदानः पाने का आज तक इंतजार कर रहा है। शायद सुप्रीम कोर्ट अब उन पर रहम कर दें।

वरिष्ठ दलित नेता डी०सी० कपिल ने कहा कि 80 की दहाई तक दलितों की वही दुर्दशा थी जो आज कमजोर तबके के मुस्लिमों की है।

दिनों-दिन अत्याचार का ग्राफ इन पर बढ़ता चला जा रहा, जबकि 1989 में बने ₹अत्याचार निवारण एक्ट₹ में दलितों एवं आदिवासियों को शामिल करने के कारण हमारे समुदाय पर अत्याचार होना बहुत कम हुआ है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की है कि पसमांदा समाज को ₹अत्याचार निवारण एक्ट 1989₹ मे शामिल किया जाए, ताकि इनके खिलाफ गलत एवं उत्तेजित नारों मारपीट, माबलिंचिग, दंगे-फसाद, महिलाओं एवं धार्मिक स्थलों से छेड़खानी पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए सरकार को ना तो बड़ा संशोधन करना है और ना ही बड़ा बजट चाहिये लेकिन दंगे-फसाद की सियासत, जरूर खत्म होगी। इस अवसर पर मेहदी हसन मंसूरी, एडवोकेट ताहिर हुसैन, अधिवक्ता वासी अहमद, डॉ इक़रार भारती, शब्बीर अहमद मंसूरी, युसूफ मंसूरी, एहतशाम बाबर, नाज़मि इलाही, संजय गुजर, गौतम राणे सागर, मौलाना गुलज़ार एवं हाजी नाज़मि वगैरह ने संबोधित किया।

नोएडा में ड्राइविंग टेस्ट की नई व्यवस्था में 80 प्रतिशत लोग फेल, एडवांस ट्रैक पर नहीं चला पा रहे गाड़ी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में अब Driving Licence बनवाना मुश्किल हो गया है। अभी तक लोग परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की आड़ में बिना ड्राइविंग दक्षता के भी आसानी से डीएल बनवा ले रहे थे। यहीकारण है कि आए दिन सड़कें हादसों से लाल हो रही है। जिले में 2020 से अब तक 1882 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है।

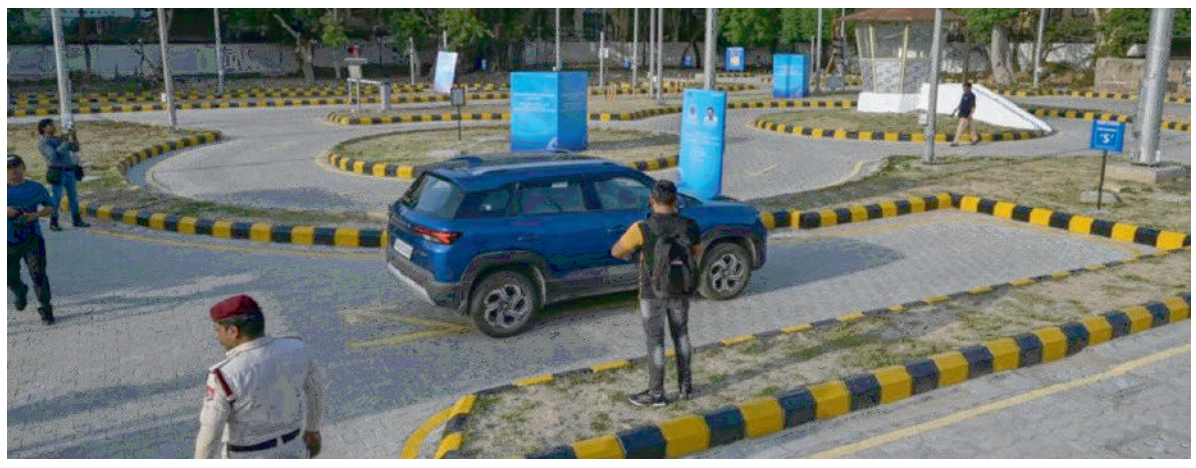

नोएडा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शुरू एडवांस ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम व ट्रैक की नई व्यवस्था में 80 प्रतिशत लोग फेल हो रहे हैं।

पुरानी व्यवस्था की तुलना में प्रतिदिन बनने वाली डीएल की संख्या में भी 97 प्रतिशत की कमी आई है। इससे साबित हो गया है कि अब तक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में खुलेआम मानकों का उल्लंघन हो रहा था।

रियल टाइम निगरानी

आधारित नई व्यवस्था में एक से सात अगस्त तक 134 लोगों ने स्थायी डीएल बनाने के लिए परीक्षा दी। इसमें से मात्र 27 लोग ही पास हो पाए। जहां पर पहले प्रतिदिन औसतन 125 डीएल बन रह थे। वहीं, अब यह आंकड़ा 19 पर सिमट गया है।

बिसाहड़ा में निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र शुरू

जिले में प्रदेश का पहला निजी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र बिसाहड़ा में एक अगस्त से ही शुरू हुआ है। यहां पर एडवांस ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम व ट्रैक स्थापित किया गया है। ट्रैक पर सेंसर युक्त कैमरे लगे हैं। इनकी सहायता से टेस्ट के दौरान आपकी ऑनलाइन निगरानी हो रही होती है।

इस दौरान तय मानकों के अनुसार ड्राइविंग करने पर ही आपको लाइसेंस जारी होता है। गलत वाहन चलाने पर आपका लाइसेंस रद हो जाता है। ड्राइविंग ट्रैक की गतिविधि एआरटीओ, आरटीओ से लेकर उपायुक्त व आयुक्त स्तर तक के शीर्ष अधिकारी एक क्लिक पर देख सकते हैं।

साथ ही इसका रिकार्ड भी स्टोर रहता है। ऐसे में किसी भी सामन्य परिस्थिति में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जाती है। अभी तक की व्यवस्था में परिवहन विभाग के संभागीय निरीक्षक (आरआइ) आपका ड्राइविंग टेस्ट लेते थे, लेकिन जिले में तय मानक वाला ट्रैक नहीं होने से ड्राइविंग दक्षता का पूरी तरह परीक्षण नहीं हो पाता था।

सड़क हादसों में आएगी कमी

सड़क हादसों के प्रमुख कारणों में खराब ड्राइविंग एक है। नई व्यवस्था में जिस पूर्णता के साथ चालक को ड्राइविंग मानकों की कसौटी पर परखा जा रहा है। इससे ठीक से वाहन चलाने में सक्षम लोगों का ही डीएल बन पाएगा।

साथ ही लोगों को ड्राइविंग के दौरान सामना करने वाले विपरीत परिस्थिति का भी आभास रहेगा। डीएल टेस्ट में शामिल होने से पहले लोग ठीक से प्रशिक्षण लेंगे। इससे चालक की गलती से होने वाले सड़क हादसों में काफी हद तक की आने की उम्मीद है।

दलालों के सिंडीकेट पर लगी लगाम

अब तक चली आ रही व्यवस्था में अक्सर परिवहन विभाग पर मानकों के अनुरूप टेस्ट के बिना डीएल बनाने के आरोप लगते रहे हैं। दलालों के बिना टेस्ट डीएल बनवाने के भी मामले सामने आते रहे हैं।

अधिकारियों पर भी सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन नई व्यवस्था में बाहरी व्यक्तियों की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई है। अब आम से लेकर खास हर व्यक्ति को ड्राइविंग ट्रैक पर मानकों के अनुसार वाहन चलाना ही पड़ेगा।

किया था उजागर

परिवहन विभाग में डीएल बनाने के नाम पर चल रहे खेल को उजागर करते हुए 15 मार्च को स्टिंग आपरेशन किया था। इसमें दलालों ने कैमरे पर पांच हजार रुपये में बिना टेस्ट लाइसेंस बनाने की बात कही थी। नई व्यवस्था ने स्टिंग आपरेशन को पुष्ट करते हुए विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर मोहर लगाई है।

नई व्यवस्था के तहत एडवांस ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। इसमें परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में कमी आइ है। इसका उद्देश्य ही ड्राइविंग टेस्ट में लोगों को उच्च मानकों पर परखना है। - डॉ. सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन

दो पैर और एक हाथ गंवाने वाले दिव्यांग का ई-रिक्शा चलाने का वीडियो वायरल, तरह-तरह के कमेंट कर रहे लोग

वीडियो में युवक के दोनों पैर और एक हाथ नहीं हैं और वह ई-रिक्शा की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। एक युवक वीडियो में बता रहा है कि उसने ई-रिक्शा की ब्रेक हैंडल पर कर रखी हैं।

नगर के बुलंदशहर रोड पर एक दिव्यांग युवक के ई-रिक्शा चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कुछ लोगों ने एक दिव्यांग युवक के ई-रिक्शा चलाने का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल किया।

वीडियो में युवक के दोनों पैर और एक हाथ नहीं हैं और वह ई-रिक्शा की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। एक युवक वीडियो में बता रहा है कि उसने ई-रिक्शा की ब्रेक हैंडल पर कर रखी हैं। इसी हाथ पर स्पीड देने का भी उपकरण है। इसी एक हाथ के जरिए वह ई-रिक्शा चलाकर अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। वीडियो पर कमेंट कर रहे बहुत से लोगों ने इस दिव्यांग युवक का जज्बा बताते हुए उसे प्रोत्साहित किया है। जबकि, कुछ लोगों का कहना है कि इसके कारण किसी भी दिन दुर्घटना भी हो सकती है।

एक हाथ से ई-रिक्शा का संचालन करना बहुत अधिक कठिन है। मामले में एआरटीओ प्रशासन छवि चौहान का कहना है कि वीडियो के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। यदि इस प्रकार से कोई ई-रिक्शा का संचालन कर रहा है तो वह गलत है। इसकी जांच अवश्य कराई जाएगी।

उधार के 40 लाख रुपये मांगने गए मामा को भांजे ने बनाया बंधक, मारी गोली

नोएडा में एक मामा को अपने उधार के रुपये मांगना भारी पड़ गया। आरोपी ने अपने मामा को रुपये देने के बहाने घर पर बुलाया और उसे बंधक बना लिया। फिर उसने मामा को मारने की नीयत से गोली मार दी। आरोपी ने मामा से सात वर्ष पहले चालीस लाख रुपये उधार ले लिए थे जो अभी तक नहीं दिए।

नोएडा। दनकौर क्षेत्र के जगनपुर अफजपुर गांव में एक युवक द्वारा अपने मामा को गोली मारने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उधारी के 40 लाख रुपये मांगने आए मामा को पहले तो कमरे में बंधक बनाया उसके बाद गोली मार दी गई। गोली पीड़ति के कंधे में फंस गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में भर्ती कराया गया है। घायल के भाई द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

सात साल पहले दिए थे 40 लाख

बागपत जिले के जिले के कानोली बिचपड़ी गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि दनकौर कोतवाली क्षेत्र के जगनपुर गांव में उनकी ताऊ की लड़की की ससुराल है। उनका कहना है कि रिश्ते में लगने वाले भांजे को उनके बड़े भाई सुरेंद्र ने सात वर्ष पहले करीब 40 लाख रुपये उधार दिए थे।

कई वर्षों से रुपये मांग रहा पीड़ित

पीड़ति काफी समय से अपने रुपयों की मांग कर रहा था। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी रुपयों को लेकर मामा और भांजे में कहासुनी हो गई थी, लेकिन उस समय जगनपुर गांव के ही कुछ लोगों ने समझौता करा दिया था।

रुपये देने के बहाने बुलाया

वीरेंद्र का कहना है कि षड्यंत्र के तहत शुक्रवार की रात आरोपी भांजे ने फोन करके उनके भाई को रुपये देने के लिए बुलाया था। जिसके चलते उनके भाई शनिवार की सुबह घर पहुंच गए थे। आरोप है कि आरोपित भांजे ने अपने पिता और परिवार के दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके भाई को एक कमरे में बंधक बना लिया।

मारने की नीयत से मारी गोली

इसके बाद उनसे मारपीट की गई। जब पीड़ति द्वारा विरोध किया गया तो जान से मारने की नीयत से गोली मार दी गई जो सुरेंद्र के कंधे में लगकर फंस गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में पुलिस को मामले की सूचना दी और घायल को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि अधिक खून बहने के कारण घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ति स्वजन द्वारा कोतवाली पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की गई। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बिल्डिंग की 34वीं मंजिल पर कॉकटेल पार्टी, 30 से ज्यादा लड़के-लड़कियां शामिल; जब पहुंची पुलिस तो...

नोएडा की सुपरनोवा सोसाइटी की एक बिल्डिंग की 34वीं मंजिल के फ्लैट में कॉकटेल पार्टी चल रही थी। इस दौरान नीचे शराब की बोतलें भी फेंकी गई। इसके बाद स्थानीय लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी पुलिस ने 30 से ज्यादा युवक-युवतियों को हिरासत में लिया है। मौके से शराब की बोतलें जूस के पैकेट हुक्का व नशा के अन्य सामान बरामद किए।

नोएडा। सेक्टर-126 थाना क्षेत्र के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी के 34वें फ्लोर के थ्री-बीएचके फ्लैट में शुक्रवार रात कॉकटेल पार्टी कर रहे युवक-युवतियों ने नीचे शराब की बोतल फेंक दी। गनीमत रही कि वह किसी को लगी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो जाता।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 30 से ज्यादा युवक-युवतियों को हिरासत में लिया। मौके से शराब की भरी व खाली बोतलें, जूस के पैकेट, हुक्का व नशा के अन्य सामान बरामद किए।

शराब की बोतल मिली

स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे चौथी मंजिल के किड्स पूल टू प्ले एरिया के पास किसी फ्लैट से शराब की बोतल फेंकी गई। इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि फ्लैट संख्या-3401 ईस्ट में शोरगुल हो रहा है। लोगों ने इसकी पुलिस को सूचना दी।

30 ज्यादा युवक-युवतियां हिरासत में

पुलिस उस फ्लैट पर पहुंची तो उसमें 30 से ज्यादा युवक-युवतियां कॉकलेट पार्टी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मौके से बरामद शराब की भरी व खाली बोतलें, हुक्का, जूस के पैकेट व नशे के अन्य सामान को अपने कब्जे में कर लिया। सोसाइटी के लोगों ने मामले की पुलिस को लिखित शिकायत भी दी।

जन्मदिन पार्टी के बहाने दिलाया प्रवेश

विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, नोएडा के एक नामी विश्वविद्यालय से बीकॉम कर रहे तीन युवक 3401 ईस्ट फ्लैट में किराए पर रहते हैं। शुक्रवार को फ्लैट में जन्मदिन पार्टी के नाम पर बाहरी युवक-युवतियों को सोसाइटी में प्रवेश दिलाकर फ्लैट में बुलाया था। सुपरटेक ग्रुप के निदेशक नीतिश अरोड़ा ने बताया कि फ्लैट में रह रहे युवक ने जन्मदिन पार्टी के नाम पर गेस्ट को भेजने की अनुमति मांगी थी।

लोग बोले रेव पार्टी थी

इंटरनेट मीडिया पर इस मामले का वीडियो व फोटो प्रसारित हुआ है। उनमें युवक-युवतियां नशे में दिख रहे हैं। मौके पर शराब की बोतलें, हुक्का आदि दिख रहा है। सूत्रों की मानें तो पुलिस को मौके से ड्रग्स भी बरामद हुआ। वह पुड़िया में मिले सफेद पदार्थ की जांच करा रही है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह रेव पार्टी थी। पुलिस को मामले की जांच करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

दूसरी ओर, एक्स पर लोगों ने युवा पीढ़ी को गलत दिशा में जाने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।

पेशेवर या कलेक्शन कर हुई पार्टी

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि पार्टी में शामिल होने के लिए मैसेज भेजे गए थे। रुपये कलेक्ट कर पार्टी का आयोजन किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

500 से 800 रुपये शुल्क लेकर प्रवेश दिया गया। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आयोजन पेशेवर तौर पर तो नहीं किया गया। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त रामबदन सिंह व अपर पुलिस उपायुक्त मनीष मिश्र कुछ भी कहने से बचते रहे।

वक्फ बोर्ड की आड़ में जमीन कब्जाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी

संजय सक्सेना

मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से एक दिन पहले कहा कि विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। विधेयक पेश किए जाने के बाद सरकार ने इसे व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति के लिए प्रवर समिति को भेज दिया है।

वक्फ और वक्फ की संपत्तियों को लेकर हिंदुस्तान में अक्सर सही-गलत चर्चा होती रहती है। हममें से अधिकांश लोगों ने वक्फ का नाम तो सुना है, लेकिन वह इसके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं। वक्फ होता क्या है। किसी मस्जिद या दूसरे धर्मस्थल के वक्फ होने का मतलब क्या है? और क्या मोदी सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड के संविधान में तब्दीली की कोशिशों का असर मुस्लिम धर्मस्थलों के स्टेटस पर पड़ सकता है? चूंकि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी वक्फ बोर्ड ही है। इसलिए हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भारत में इस्लाम की आमद के साथ वक्फ के उदाहरण मिलने लगे थे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। मुगल शासन काल में क्योंकि ज्यादातर संपत्ति राजा महाराजाओं के पास ही होती थी, इसीलिए प्रायः वही वाकिफ होते, और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाईं, वो सारी वक्फ हुईं और उनके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रहीं।

इसके पश्चात 1947 में आजादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात उठने लगी। इस तरह 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था, जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गईं। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद, इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। 2013 में मनमोहन सरकार के समय इसमें कई संशोधन करके इसे पूरी तरह से तानाशाही रूप दे दिया गया। फिलहाल जो व्यवस्था है, वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है, इसमें सबसे खतरनाक संशोधन यह था कि वक्फ बोर्ड जिस किसी सम्पति को अपना बता दे तो फिर वह उसकी बिना किसी जांच पड़ताल के हो जाती है और जिसकी सम्पति छीनी जाती है, वह कोर्ट या पुलिस के पास भी अपनी फरियाद लेकर नहीं जा सकता है। प्रायः मुस्लिम धर्मस्थल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आते हैं. लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है.

वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए मोदी सरकार ने आठ अगस्त 2024 को लोकसभा में दो विधेयक पेश किये। पहले विधेयक के जरिये सरकार मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को समाप्त करने को कटिबद्ध लगती है, जबकि दूसरे से मुसलमान वक्फ अधिनियम 1995 में 44 संशोधन किए जाएंगे। सरकार इस विधेयक में बोहरा-आगाखानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करेगी और किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने के अधिकार से संबंधित धारा 40 को समाप्त कर देगी।

मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक संसद में पेश करने से एक दिन पहले कहा कि विधेयक लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। विधेयक पेश किए जाने के बाद सरकार ने इसे व्यापक विमर्श और सर्वसम्मति के लिए प्रवर समिति को भेज दिया है। दूसरे विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता विकास अधिनियम करने का प्रावधान है। इसमें वक्फ बोर्डों के केंद्रीय परिषद और ट्रिब्यूनल की संरचना में व्यापक बदलाव लाने का भी प्रावधान है। मसलन केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाया जाएगा। इसके अलावा कानून में संशोधन के बाद अब वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को 90 दिन के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए सर्वे कमिश्नर का अधिकार अब जिला कलेक्टर या उसके की ओर से नामित डिप्टी कलेक्टर के पास होगा।

विधेयक की खास बातों पर नजर डाली जाए तो मोदी सरकार वक्फ अधिनियम, 1923 को वापस लेगी। पारदर्शिता, बेहतर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 44 संशोधन किये जायेंगे। जिसके द्वारा आगाखानी व बोहरा वक्फ को परिभाषित किया जाएगा। पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने वालों की संपत्ति वक्फ हासिल कर सकेगा। वक्फ के धन से विधवा, तलाकशुदा व अनाथों के कल्याण के लिए सरकार के सुझाए तरीके से काम करने होंगे। संपत्ति वक्फ को देने के दौरान उत्तराधिकारियों और महिलाओं के अधिकार नहीं छीने जा सकेंगे। वहीं रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों को 6 माह में पोर्टल पर डालना होगा। वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले भू राजस्व, सेस, उसका रेट, कर, आय, कोर्ट मामले की जानकारी भी बतानी होगी।सरकारी संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा

वक्फ बोर्ड में जो बदलाव होंगे उसके अनुसार मुसलमान वक्फ कानून 1923 खत्म होगा। वक्फ अधिनियम होगा एकीकृत वक्फ प्रबंधन कानून, धारा 40 होगी खत्म, जिससे किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिल जाता है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार यूपीए-2 में मनमोहन सिंह सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को किसी की भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने और वक्फ बोर्ड के निर्णयों को किसी भी कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार खत्म करने जैसे बदलाव किए गए थे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार तब से मुस्लिम समाज से जुड़े व्यक्तियों व संगठनों की करीब 60 हजार शिकायतें सरकार के पास लंबित हैं। इन सभी शिकायतों में वक्फ बोर्ड में भारी अनियमितता व जबरन संपत्ति पर कब्जा जैसी समान बातें थीं। संशोधन विधेयक में वक्फ परिषद में भी बदलाव का प्रावधान है। मसलन परिषद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होंगे।तीन सांसद, मुसलमानों के तीन प्रतिनिधि, मुस्लिम कानून के तीन जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दो पूर्व जज, एक वरिष्ठ वकील, देश की चार नामचीन हस्तियां व केंद्र सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त स्तर के अधिकारी व दो महिलाएं इसकी सदस्य होंगी।

उधर, विपक्षी दलों ने बिल पेश होने से पहले ही सरकार से आग्रह किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को पेश किये जाने के बाद इस पर विचार करने के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। वहीं सरकार ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की भावना का आकलन करने के बाद वह इस पर फैसला करेगी। इसी क्रम में मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया, वह इस दृष्टि से सही कदम है, क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और संभवतः दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन-फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी गई।

ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और फिर कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है और वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं? यह अब यक्ष प्रश्न होगा।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

अमारा राजा और पियाजियो ने ईवी बैटरी उत्पादन के लिए किया करार

परिवहन विशेष न्यूज

अमारा राजा की सहायक कंपनी अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलॉजीज ने इटली के पियाजियो ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी पियाजियो व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शनिवार, 10 अगस्त को घोषित यह समझौता पियाजियो के इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और भविष्य के दोपहिया वाहनों के लिए लिथियम-आयन सेल, बैटरी पैक और चार्जर के विकास और आपूर्ति के लिए किया गया है।

एमओयू के तहत अमारा राजा तेलंगाना के दिविटिपल्ली में अपनी गीगाफैक्ट्री में लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम-आयन सेल और चार्जर बनाएगी। कंपनी का कहना है कि यह कदम स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र के विकास का समर्थन करने की अमारा राजा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

यह करार 2020 में शुरू हुई साझेदारी पर आधारित है, जिसके दौरान अमारा राजा ने पियाजियो को 50,000 एनएमसी लिथियम-आयन बैटरी पैक और ईवी चार्जर की आपूर्ति की थी। इन उत्पादों का सामूहिक रूप से 120 करोड़ किलोमीटर से अधिक उपयोग किया जा चुका है।

अमारा राजा ग्लोबल एलएफपी प्रौद्योगिकी को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए गोटियन-इनोबैट-बैटरीज (जीआईबी) के साथ तथा एनएमसी प्रौद्योगिकी के लिए जियांग्सू हाईस्टार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ भी काम कर रही है।

यह समझौता ज्ञापन अमारा राजा के ग्राहक योग्यता संयंत्र (सीक्यूपी) और दिविटिपल्ली में इसके गीगाकॉरिडोर की आधारशिला रखने के साथ हुआ। कस्टमर क्वालिफिकेशन प्लांट अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही तक चालू हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के परीक्षण और सत्यापन की सुविधा प्रदान करेगा।

कार में गलती से पेट्रोल की जगह डीजल चले जाने पर क्या करें? सावधानी बरतने से नहीं खराब होगा इंजन

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आपको अपनी गलती तुरंत पता चल गई है तो गाड़ी इग्निशन चालू करने से बचें। अपनी कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और अपने कार निर्माता की ग्राहक सेवा से संपर्क करें। डीजल कार में पेट्रोल भरना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सर्विस सेंटर पेट्रोल निकालने के बाद फ्यूल लाइन्स को फ्लश और साफ करेगा। पेट्रोल की जगह डीजल जाने पर नुकसान आमतौर पर सीमित होता है।

नई दिल्ली। गाड़ी फ्यूल-अप कराते समय अगर आपने गलती से पेट्रोल की जगह डीजल या डीजल की जगह पेट्रोल चला जाता है, तो तुरंत सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आपको अपनी गलती तुरंत पता चल गई है, तो गाड़ी इग्निशन चालू करने से बचें। अपनी कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और अपने कार निर्माता की ग्राहक सेवा से संपर्क करें। RSA आपको अपने वाहन को निकटतम सर्विस स्टेशन पर ले जाने और ईंधन निकालने में मदद करेगा। आइए, जान लेते हैं कि गलत फ्यूल चले जाने पर क्या करना चाहिए?

डीजल की जगह पेट्रोल

डीजल कार में पेट्रोल भरना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सर्विस सेंटर पेट्रोल निकालने के बाद फ्यूल लाइन्स को फ्लश और साफ करेगा। साथ ही ईंधन फिल्टर को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि, अगर डीजल कार के टैंक में केवल 5% पेट्रोल गया है, तो आप बाकी हिस्से में डीजल भर सकते हैं। इतनी कम मात्रा में डीजल होने से इंजन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

पेट्रोल की जगह डीजल

आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल चला जाता है, तो नुकसान आमतौर पर सीमित होता है। पेट्रोल, डीजल की तुलना में कहीं अधिक रिफाइन होता है और इंजन के स्पार्क प्लग से निकलने वाली चिंगारी से इग्निशन बनाता है।

अगर पेट्रोल कार के इंजन को उसके टैंक में डीजल के साथ क्रैंक किया जाता है, तो स्पार्क प्लग और फ्यूल सिस्टम डीजल से बंद हो जाएगा। साथ ही फ्यूल फिल्टर भी खराब हो जाएगा। ऐसे में कार रुक जाएगी और इंजन में मिसफायर होगा और बहुत अधिक धुआं निकलेगा। ऐसे में आपको डीजल को पूरी तरह साफ करना होगा।

आनंद महिंद्रा की ऑटो कंपनी केरल में लगाएगी इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री

देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा केरल में इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्री लगा सकती है। इसके लिए कंपनी केरल सरकार से बातचीत कर रही है। दक्षिण भारत का केरल राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में सबसे आगे है।

रॉयटर्स की एक खबर के अनुसार एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी और शांक्सी की एक चीनी कंपनी ने 3 बिलियन डॉलर का संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति जताई है। इस उद्यम के तहत गुजरात में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस सौदे को केंद्र की मंजूरी का इंतजार है। लेकिन महिंद्रा ने इस खबर को 'निराधार' बताया है।

केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'प्लांट लगाने के लिए बातचीत चल रही है। देश के बाहर से कुछ कंपनियां केरल आ रही हैं, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा बाजार है। हम इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। महिंद्रा अगले सप्ताह बातचीत के लिए आएगी।"

उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल रही तो अगले साल फरवरी 2025 में प्रस्तावित वैश्विक

निवेशक शिखर सम्मेलन से पहले केरल में औद्योगिक क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों के मामले में केरल इस समय देश में सबसे आगे है। बीएनपी पारिबा की एक रिपोर्ट के अनुसार केरल में कुल वाहनों में से 5.2 प्रतिशत ईवी हैं।

बीएनपी पारिबा की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कुल वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी 3.2% है, जबकि कर्नाटक में यह केवल 3.1% है। ई-टू-व्हीलर्स के मामले में भी केरल 13.5% के साथ सबसे आगे है। कर्नाटक में ई-टू-व्हीलर्स की हिस्सेदारी 11.5%, महाराष्ट्र में 10.1% और दिल्ली में 9.4% है।

विझिंजम जैसे कंटेनर पोर्ट होने का फायदा केरल को भी मिल रहा है। उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा, 'ईवी बिक्री के मामले में केरल शीर्ष पर है। हमने चार्जिंग के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया है। सरकारी कंपनी केरल ऑटोमोबाइल ने भी इलेक्ट्रिक ऑटो बनाए हैं। इसके लिए हम कुछ कंपनियों से फैक्ट्री लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।'

महिंद्रा एंड महिंद्रा के अधिकारी से केरल योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्पष्टीकरण जारी कर गुजरात योजना के बारे में रिपोर्टों को निराधार बताया।

फरीदाबाद में कंपनी ने स्टेपनी कवर एक्टिविटी के साथ किया अपने उत्पाद का प्रचार

परिवहन विशेष न्यूज

फरीदाबाद में जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक ने ई-रिक्शा चालकों को वाहन के रखरखाव, पुराने व नए ई-रिक्शा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीके, जैसे मोटर की सुरक्षा कैसे करें, पानी से कैसे बचाएं, वाहन को ओवरलोड न करें, मोटर गर्म हो रही है तो एजेंसी को दिखाएं, मीटर वाटर प्रूफ नहीं है तो उसे ढक कर रखें, वाहन को बार-बार चार्जिंग पर न लगाएं, वाहन की समय पर सर्विस करवाएं ताकि बैटरी अच्छी तरह से और लंबे समय तक चले, वाटर प्रूफ एक्सीलेटर लगवाएं और केवल भारतीय ब्रांड का ही उपयोग करें आदि के बारे में जानकारी दी।

ऑटो-लेक इलेक्ट्रिक ने अपने उत्पादों की विशेषताओं के बारे में बताया। लोगों ने इसमें काफी रुचि दिखाई और कंपनी के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही कंपनी ने 300 से अधिक ई-रिक्शा में स्टेपनी कवर लगाकर लोगों को अपने ब्रांड के बारे में जागरूक किया।

कंपनी ने यह गतिविधि ओल्ड फरीदाबाद, बड़कल चौक, सेक्टर 28-29 की मार्केट के पास आयोजित की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटर, कंट्रोलर और डिफरेंशियल के बारे में जान सकें। कंपनी ने कहा कि आने वाले समय में हम अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां चलाकर ई-रिक्शा चालकों को जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे।

उचाना में पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुला

परिवहन विशेष न्यूज

हरियाणा के जींद जिले के उचाना में दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के कार्यालय परिसर में जींद जिले का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। उचाना वासियों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 352 से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है कि जींद जिले का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उचाना में दक्षिण हरियाणा बिजली निगम के कार्यालय परिसर में स्थापित किया गया है।

शुरुआत में बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर या परिसर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, ताकि ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो सके। फिलहाल होटलों और पेट्रोल पंपों के लिए टेंडर जारी नहीं किए गए हैं। परीक्षण के तौर पर जींद से नरवाना तक नेशनल हाईवे 352 पर चार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन सेफ्फी कंपनी ने लगाया है और जींद जिले का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। इससे पहले जींद जिले में कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नहीं था।

नेशनल हाईवे 352 पर चार चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। पहला चार्जिंग स्टेशन उचाना में बिजली विभाग के परिसर में बनाया गया है। 2 से 3 दिन में चार्जिंग स्टेशन लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि बिजली विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को कनेक्शन दे दिया गया है। उचाना बिजली विभाग के जेई दर्शन सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से ईसीएस कनेक्शन दिया गया है और इसे सेफ्फी कंपनी ने लगाया है। बिजली विभाग ने यह कनेक्शन शुक्रवार, 09 अगस्त को ही शुरू किया है। बाकी वाहनों के लिए सेवा कब शुरू होगी, यह तय करना कंपनी का काम है।

महिंद्रा की गाड़ियों की बिक्री में हुई 15% वृद्धि, स्कॉर्पियो रही टॉप पर

महिंद्रा ने जुलाई 2024 में 15% वार्षिक और 4% मासिक वृद्धि दर्ज की है। इससे कंपनी की भारतीय मार्केट में हिस्सेदारी 12.1% हो गई है। जुलाई 2024 में महिंद्रा की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी स्कॉर्पियो/एन रही और सबसे कम मॉडल की बिक्री महिंद्रा मराजो की हुई। आइए जानते है कि जुलाई 2024 में सालाना और मासिक के आधार पर महिंद्रा की गाड़ियों की कितनी बिक्री हुई।

नईदिल्ली। मारुति, हुंडई और टाटा मोटर्स के बाद भारत में चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली ऑटोमेकर कंपनी महिंद्रा ने जुलाई 2024 में शानदार बिक्री दर्ज की है। कंपनी ने 15% वार्षिक और 4% मासिक वृद्धि दर्ज की है, जिससे कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 12.1% हो गई है। आइए जानते हैं कि महिंद्रा की किस गाड़ी की कितनी बिक्री हुई।

जुलाई 2024 सालाना आधार पर महिंद्रा की बिक्री

जुलाई 2024 में सालाना आधार पर महिंद्रा की बिक्री 41,523 यूनिट रही, जो जुलाई 2023 में बेची गई 36,205 इकाइयों की तुलना में यह 15% ज्यादा रही। स्कॉर्पियो की सालाना बिक्री में 16% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। जुलाई में कंपनी ने स्कॉर्पियो/एन पर वेंटिलेटेड सीटों और ऑटो डिमिंग IRVMs के साथ अपग्रेड किया था। जिससे इसकी खरीदारी बढ़ी है। महिंद्रा XUV3XO बिक्री में 121% की वार्षिक वृद्धि देखने के लिए मिली है। XUV3XO, जो वर्तमान में सब 4-मीटर एसयूवी की लिस्ट में नंबर 5 पर है। जुलाई 2024 में XUV700 की बिक्री में सुधार देखने के लिए मिला है। इसकी सालाना आधार पर बिक्री 26% अधिक रही।

मलप्पुरम ऑटो चालक को खराब इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए मिलेगा 1 लाख रुपये का मुआवजा

परिवहन विशेष न्यूज

कलिकावु (मलप्पुरम): कलिकावु ऑटो चालक ननबन शम्सुद्दीन की दो साल की कानूनी लड़ाई सफल रही है। केरल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने राज्य के स्वामित्व वाली केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड को उसके क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा को बहाल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कंपनी को उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के लिए 25,000 रुपये देने का आदेश दिया गया है।

2022 में शम्सुद्दीन ने शोरानूर स्थित केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड से एक इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा खरीदा। सिर्फ़ दो हफ़्तों के भीतर ही वाहन सड़क पर चलते समय खराब हो गई। हालाँकि कंपनी ने शुरू में समस्या को ठीक कर दिया, लेकिन बैटरी खराब होने और चार्ज न होने के कारण ऑटो जल्द ही फिर से खराब हो गया। बैटरी बदलने की लागत लगभग 1 लाख रुपये आंकी गई थी। जिले में सर्विस सेंटर की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया, जिससे बार-बार ब्रेकडाउन हुआ और मरम्मत में देरी हुई।

जब कंपनी ने खराब बैटरी बदलने से इनकार कर दिया, तो शम्सुद्दीन ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और निर्देश दिया कि शम्सुद्दीन के घर पर खड़ी इलेक्ट्रिक रिक्शा को वापस ले लिया जाए, उसकी मरम्मत की जाए और 60 दिनों के भीतर उसे लौटा दिया जाए। वाहन को ऑटोमोबाइल इंजीनियर द्वारा सेवाक्षमता का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएं। आयोग ने शम्सुद्दीन को दो साल तक वाहन न चला पाने के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, साथ ही कानूनी खर्च के लिए 25,000 रुपये भी दिए।

इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रिक रिक्शा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, तो शम्सुद्दीन को वाहन की मूल लागत 3,12,000 रुपये वापस की जाएं। पुनर्भुगतान में किसी भी देरी के मामले में नौ प्रतिशत ब्याज दर भी लागू होगी।

अब विकसित भारत की डगर

डा. जयंतीलाल भंडारी

भारत के विकसित बनने संबंधी विषय पर विश्व बैंक के द्वारा एक अगस्त को प्रस्तुत रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाए जाने का संकल्प अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है'

इन दिनों देश के कोने-कोने में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के मद्देनजर विचार मंथन का दौर दिखाई दे रहा है। यह कहा जा रहा है कि विकसित भारत का संकल्प चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं है और भारत इसे प्राप्त कर सकता है। हाल ही में नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित देश बनाने के लिए कई अनुकूलताएं भारत के पास हैं। चूंकि यह दशक तकनीक और भू-राजनीतिक बदलाव का है, अतएव भारत को इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जिससे भारत विकसित देश की डगर पर आगे बढ़े। नीति आयोग के पदेन सदस्य कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के मद्देनजर कृषि सेक्टर की अहम भूमिका होगी। गौरतलब है कि नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने को लेकर प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण पत्र में कहा गया है कि 'जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता' के तीन स्तंभों पर विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहा गया है कि पिछले 70 वर्षों में मुश्किल से एक दर्जन मध्यम आय वाले देश ही उच्च आय वाले विकसित देश बन पाए हैं। ऐसे में विकसित भारत के लिए कई बड़े लक्ष्य की चुनौतियों के बीच भारत को विकसित देश बनाने की डगर पर आगे बढ़ा जाएगा। कहा गया है कि भारत को एक विकसित देश बनने के लिए 18000 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के साथ 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता है।

एक विकसित देश के मद्देनजर विकसित भारत को महज ऐसी आर्थिक एवं वित्तीय विशेषता तक सीमित नहीं रहना होगा, वरन्-विकसित भारत के मद्देनजर देश के व्यक्तियों के लिए जीवन की अच्छी गुणवत्ता का संकेत भी देना होगा और एक ऐसा सक्षम समाज बनाना होगा जो जीवंत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण हो। देश को विकसित भारत बनाने के लिए कई और महत्वपूर्ण सेवाओं और सुविधाओं की जरूरत होगी। देश में प्रत्येक नागरिक के पास गुणवत्तापूर्ण आवास, 24 घंटे शुद्ध पेयजल और बिजली आपूर्ति, हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड और बैंकिंग सुविधाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच जरूरी होगी। देश में उच्च जीवन प्रत्याशा के साथ एक स्वस्थ जीवन और विश्व स्तरीय और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच जरूरी होगी। देश में सार्वभौमिक साक्षरता और बहु-विषयक, जीवन भर सीखने के साथ सभी के लिए सार्थक शिक्षा और कौशल, पूर्ण रोजगार और समृद्ध आजीविका, उद्यमशीलता के अवसरों वाले समाज का निर्माण किया जाना होगा। देश में एआई सक्षम चिकित्सा, शिक्षा और कृषि जैसी उन्नत तकनीकों सहित सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होना जरूरी है। देश में सार्वजनिक परिवहन, डीपीआई और दूरसंचार सहित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा निर्मित किया जाना होगा। देश को वैश्विक आर्थिक विकास का चालक बनाने और वैश्विक प्रतिभा, व्यापार और पूंजी का चुंबक बनाया जाना होगा। देश के शहर और बाजार दुनिया के सबसे बड़े और शीर्ष व्यापारिक और वित्तीय केंद्रों में रेखांकित होने चाहिए। देश मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं, अनुसंधान और नवाचार में आगे होना चाहिए। देश में एक जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था जरूरी होगी जिसमें ग्रामीण जीवन स्तर शहरी क्षेत्रों के बराबर हो। साथ ही औसत ग्रामीण आय (कृषि और गैर-कृषि दोनों) देश की प्रति व्यक्ति आय के बराबर हो। विकसित भारत के लिए यह भी जरूरी है कि देश दुनिया के लिए एक समावेशी और लोकतांत्रिक विकास का रोल मॉडल बने, देश वैश्विक मंचों पर एक प्रमुख सदस्य बने और वैश्विक वार्ताओं और शांति के लिए उत्प्रेरक बने।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि वित्तमंत्री सीतारमण के द्वारा वर्ष 2024-25 का आम बजट भी विकसित भारत के सपने को पूरा करने के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बजट है। इस बजट का सम्पूर्ण विश्लेषण करने के बाद दुनिया की विभिन्न प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा नए बजट से देश के विकसित भारत की डगर पर आगे बढने एवं भारत की वैश्विक साख बढने से संबंधित प्रभावी टिप्पणियां की गई हैं। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडीज, एसएंडपी, फिच आदि ने वित्त वर्ष 2024-25 के भारत के बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इस बजट के तहत राजस्व घाटा (रेवेन्यू डेफिसिट) एवं राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट) कम करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई है। निःसंदेह वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा भारत की वैश्विक साख सकारात्मक होने की जो टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं, उनके पीछे सबसे प्रमुख आधार वे प्रावधान हैं जो नए बजट को विकसित भारत के सपने को मजबूती देने वाला बजट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यद्यपि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं है। भारत को विकसित देश बनाने के लिए कई बातों पर कारगर तरीके से ध्यान देना होगा। 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और उस समय तक 18000 डॉलर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए दो अंकों की वृद्धि लगातार बरकरार रखनी होगी। इस परिप्रेक्ष्य में हम दुनिया के कई देशों को सामने रख सकते हैं। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने दशकों तक ऊंची विकास दर से विकसित देश के तमगे हासिल किए हैं। इन देशों के विकसित देश बनने में संस्थागत और सामाजिक बदलावों से भी बड़ी मदद मिली है। यदि हम ऐसे बदलावों की ओर देखें तो पाते हैं कि जहां सिंगापुर ने देश में व्याप्त अफसरशाही में सुधार किया, वहीं कोरिया ने अभिनव निजी-सार्वजनिक भागीदारी विकसित की है। इसी तरह जापान ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र में नियमन और न्यायपालिका में पूरी तरह पश्चिमी उदारवादी मॉडल अपनाने की रणनीति अपनाई। भारत में भी ऐसे संस्थागत और सामाजिक बदलाव के आधार पर उच्च वृद्धि हासिल करनी होगी। देश में ऊर्जा क्षेत्र की मुश्किलें भी दूर करनी होंगी। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना होगी।

ग्रामीण शहरी असमानता दूर करनी होगी। इन सबके साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि देश में इस समय जिस तरह पुरातन व्यवस्थाओं और सख्त अफसरशाही ढांचे की वजह से निर्णय प्रक्रिया में देरी होती है, उसमें व्यापक सुधार करना होगा। विकसित भारत के लिए जरूरी होगा कि कृषि के अतिरिक्त श्रम बल के लिए उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजित किया जाए। अब देश में काफी समय से लंबित पड़े हुए प्रशासनिक सुधारों को अमलीजामा पहनाया जाना होगा। देश में न्यायिक प्रक्रिया और कानून के प्रवर्तन में सुधार और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। देश में महिलाओं को श्रम शक्ति में अधिक भागीदारी देने और अन्य सामाजिक बदलावों को लागू करने जैसे अभियानों के लिए प्रबल राजनीतिक और सामाजिक सहमति बनाई जानी होगी। यहां भारत के विकसित बनने संबंधी विषय पर विश्व बैंक के द्वारा एक अगस्त को प्रस्तुत रिपोर्ट भी उल्लेखनीय है। इसमें विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाए जाने का संकल्प अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए भारत को मध्य आय के जाल से बाहर निकालना होगा। लगातार 7 से 10 फीसदी की विकास दर से वृद्धि करनी होगी। हम उम्मीद करें कि सरकार 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के संकल्प के मद्देनजर अधिक स्पष्ट रोडमैप के साथ कदम आगे बढ़ाएगी और देश के करोड़ों लोग राष्ट्र निर्माण और आत्म विश्वास की उच्च भावनाओं से परिपूर्ण होकर देश को विकसित देश बनाने में अपना हरसंभव योगदान देते हुए दिखाई देंगे। नागरिकों की सहभागिता से ही देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है।

संपादक की कलम से

प्रकृति में समृद्ध, विकास में पिछड़ा चंबा जिला

हिमाचल प्रदेश का जिला चंबा आजादी से पहले उत्तर पश्चिमी हिमालय का एक मुख्य रजवाड़ा हुआ करता था, जो आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में 1948 में शामिल हुआ और जिला चंबा कहलाया। हालांकि लाहौल का भी कुछ क्षेत्र चंबा रजवाड़े का भाग हुआ करता था जिसे चंबा लाहौल कहा जाता था। पंजाब-हिमाचल के पुनर्गठन के बाद कुल्लू-लाहौल का मुख्य भाग भी जब हिमाचल में शामिल हो गया तब चंबा लाहौल वाला क्षेत्र जिला लाहौल-स्पीति में डाल दिया गया। चंबा रजवाड़ा शासन के अंतर्गत अन्य पहाड़ी रजवाड़ों से विकसित और प्रगतिशील माना जाता था, जहां 1870 से पहले राजा श्री सिंह के समय आधुनिक चिकित्सालय का निर्माण हो चुका था, राजा शाम सिंह के समय जिसे 40 बिस्तर का अस्पताल बनाया गया। राज्य के दूरदराज हिस्सों को सडकों से जोड़ा गया। विद्यालय खोले गए। प्रतिभाशाली छात्रों को राज्य से बाहर पढने के लिए छात्रवृत्ति दने की व्यवस्था हुई। 1881 में एशिया का पहला कुष्ठ रोग चिकित्सा केंद्र खोला गया। राज्य में डाक व्यवस्था से संपर्क व्यवस्था खड़ी की गई। 1908 में भूरि सिंह संग्रहालय की स्थापना हुई। 1910 में जल विद्युत पॉवर हाउस बनाया गया। जब चंबा में बिजली थी, तब कांगड़ा और अन्य हिमाचली रजवाड़ों में कहीं भी बिजली नहीं थी। आजादी के समय पहाड़ी क्षेत्रों को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र कह कर पंजाब में मिलाने की बात हो रही थी, जिसके पीछे तर्क छोटे राज्य के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना संभव नहीं था। उस समय हिमाचल के पूर्वी छोर पर तीन जिले मंडी, शिमला और सिरमौर ही हिमाचल में शामिल हो रहे थे।

चंबा तो अलग-थलग पश्चिमी छोर पर था। किंतु चंबा ने प्रजामंडल के माध्यम से अलग पहाड़ी प्रदेश की मुहिम में शामिल होकर हिमाचल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिमाचल के गठन को संभव बनाया। बिलासपुर रजवाड़ा तो बाद में 1952 में हिमाचल में मिला। इसलिए चंबा के महत्व को उस समय के नेतृत्व ने समझा और समय के साथ चलने के लिए जरूरी विकास कार्य बखूबी हुए। बिजली को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का कार्य 1955 के बाद ही आरंभ हो गया। उस समय हिमाचल सी श्रेणी राज्य था जिसे पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त थी। चंबा की प्रमुख ग्रामीण सडक़ों का निर्माण शुरू हुआ। प्रदेश का पहला सामुदायिक विकास ब्लाक भटियात (चंबा) में खोला गया। स्कूलों के भवन, पटवारखाने आदि के भवन बनाए गए। दुर्भाग्य से राज्य पुनर्गठन के बाद चंबा का राजनीतिक कद छोटा होता गया। चंबा धीरे धीरे पिछड़ता गया। आज देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गणना हो रही है। हिमाचल में भी चंबा अंतिम पायदान पर खड़ा है। हालांकि जिला के पास विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता से उपलब्ध हैं। जिला में 2952 मेगावाट जल विद्युत की क्षमता है जिसमें से 1500 मेगावाट क्षमता का दोहन वर्तमान में हो रहा है। जिला का भौगोलिक स्वरूप विविधतापूर्ण है। यहां 2000 फुट से 21000 फुट तक ऊंचाई के क्षेत्र विद्यमान हैं, जहां उष्णकटिबंधीय से लेकर शीत मरुस्थलीय जलवायु उपलब्ध है। इसमें हर प्रकार की फसलों, जड़ी-बूटियों और वन उपजों का उत्पादन होता है। जिला का क्षेत्रफल 692419 हैक्टेयर है। आबादी 519080 है, जिसमें 56.65 फीसदी कर्मकार आबादी है। वन भूमि भी काफी है। कृषि क्षेत्र 70563 हैक्टेयर है। साक्षरता दर 72.17 प्रतिशत है। वर्तमान में चंबा के पिछड़ेपन के प्रमुख तीन कारण हैं : आवागमन एवं संचार व्यवस्था में कठिनाइयां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का अभाव, स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव। इन तीन कमियों के कारण जो भी व्यक्ति समर्थवान हो जाते हैं, वे यहां से दूसरी जगहों में बस जाते हैं।

कविता

मंडे से मंत्री बैठक तक

मंडे मीटिंग के बाद मंत्री मीटिंग की अवधारणा में सरकार का 'कार्यबल' सशक्त होगा। सरकार से सचिवालय और सचिवालय से प्रदेश के फासले अगर कम हो जाएं, तो राज्य का कदमताल, एक सुर-एक ताल बन जाए। हम पुनः ट्रैफिक सिग्नल की बंद बत्तियों को सुधारने के लिए टॉर्च लिए खड़े हैं, जबकि प्रशासनिक सुधारों के लिए चंद कदम निरंतरता के साथ उठाने चाहिएं। बेशक हर विभाग की जुबां मंत्री हो सकता है और अगर हफ्ते की निगाहों में रोशनी खोजी जाए, तो बैठकों का मकसद कार्रवाई में तबदील होगा, बशर्ते सरकार हाथी बनने के बजाय खरगोश बने। उपचार तो बहुत सुना मगर, हकीम की पुडिया नहीं मिली। हकीम शिमला में, दवाखाना राजधानी में, लेकिन मरीज प्रदेश के किसी न किसी छोर पर। बीमारियां छोटी हैं, मसले छोटे हैं, लेकिन आंख से पट्टियां नहीं खुल रहीं। सडक़ों को वाहनों की पार्किंग बनाने वाले जरूरतमंद मान लिए जाएं तो ट्रैफिक पर जारी आदेश भी क्या कर लेंगे। प्रदेश परंपराओं और अनुभव से भी चलता है। पिछले इतिहास, दस्तावेज और आधे-अधूरे विकास को पूरा करने से चलता है। उदाहरण के लिए स्कूल छुट्टियां काट चुके हैं, लेकिन बरसात की पढ़ाई जारी है। शिमला में शिक्षा विभाग के सामने पहली जुलाई से 31 अगस्त के बीच छुट्टियां देने की परंपरा में आंख पर जो पट्टी बंधी रही, वह आने वाली बारिशों के समुद्र में खुल जानी चाहिए। शिकायतें वही पुरानी और लंगर में वही पुराने लाभार्थी दाना चुग रहे हैं। किसी ने किसी न किसी प्रयास से जनता को संदेश दिया कि अबकी बार सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। जयराम सरकार जनमंच में शिकायतों का मंचन देखती रही, लेकिन प्रशासन ने अपना हठ नहीं छोड़ा।

हठ उन फाइलों में देखिए जो शिकायतों से दबी पड़ी हैं। पिछले सोमवार कहीं सचिवालय से दूर नगरोटा बगवां में जब चक्का जाम हो रहा था या बाजार बंद करके कोई नारा सरकार के कान के करीब गूंज रहा था, तो उसे किसने सुना। एक ट्रांसपोर्टर से हुई धोखाधड़ी का मुख्य पात्र इसी नगरोटा बगवां की प्रशासनिक बाहों से सुरक्षित बाहर निकलकर घूम रहा है, लेकिन पुलिस के पास यह फरियाद पहुंच नहीं रही। चौदह करोड़ का फ्रॉड अब तीस करोड़ की वसूली बन कर भी किस कानून व्यवस्था की सूली बना रहेगा। कैबिनेट रैंक तो नगरोटा बगवां के हिस्से भी आया, मगर पूरा शहर जो पुकार रहा है, उसे सुनेगा कौन। मंत्रियों की बैठक से आशाएं स्वाभाविक हैं और लोकतंत्र का सुनहरा पक्ष यही है कि नागरिक हमेशा उम्मीद पर जिंदा है। बहुत सारे मसले विभागीय समन्वय के हैं, इसलिए 'मंत्री बैठक' में दिशा, दृष्टि और प्रभावशाली दस्तखत देखने को मिल सकते हैं। मसलन पर्यटन की बात पर बिजली, पानी, परिवहन, कला-संस्कृति, पीडब्ल्यूडी तथा पुलिस महकमे का तालमेल, सारा परिदृश्य बदल सकता है। उद्योग के साथ राजस्व, वन, परिवहन, प्रदूषण, अग्निशमन व कराधान मंत्रालयों की सक्रियता, इसके अस्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। जिन्हें हम छोटा विभाग समझते हैं, उन्हें पारंगत करती हुई बैठकें खेल गतिविधियों, सांस्कृतिक समारोहों, दुग्ध एवं मत्स्य उत्पादन तक के महत्त्व को बड़ा बना सकती हैं। ग्रामीण के साथ शहरी विकास मंत्रालय का कदमताल हो तो टीसीपी कानून की संपूर्ण व्याख्या में पूरे प्रदेश का नियोजन होगा। मंत्रिमंडल की बैठकों की औपचारिक वेशभूषा में जो कैबिनेट रैंक बाहर रह जाते, उन्हें मंत्रियों की बैठक में दायित्व निभाने का अवसर मिलेगा। जाहिर है यह सुक्खू सरकार की निपुणता की सोच है जो मंडे बैठक से शुरू होकर मंत्रियों की बैठक की परिपक्वता में जोरदार आजमाइश करना चाहता है। जरूरी यह होगा कि मंत्रियों की बैठक का असर पूरे प्रदेश की आबोहवा में हो।

ललित गर्ग

पडोसी देशों में भारत-विरोधी सरकारों के गठन की चिन्ता

हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है।

भारत के पडोसी देशों में अस्थिरता एवं अराजकता का माहौल चिन्ताजनक है। बांग्लादेश के साथ-साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों में हुए हालिया अराजक, हिंसक एवं अस्थिरता के घटनाक्रमों से एक तस्वीर बनती है एवं एक सन्देश उभर कर आता है, वह है, चीनी के द्वारा भारत विरोधी सरकारों के गठन की साजिश। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल और तख्तापलट के बाद अस्तित्व में आई सरकारों ने भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हालात पैदा कर दिए हैं। भारत को सतर्क एवं सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल ये उठते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में हो रही इस अराजकता एवं अस्थिरता के कारण क्या हैं? यह सिर्फ एक संयोग है या फिर साजिश? क्या इसके पीछे चीन का हाथ है? क्या पाकिस्तान भी इसके लिये जिम्मेदार है? पड़ोसी देशों में पनप रही इस राजनीतिक अस्थिरता का भारत पर क्या असर होगा?

इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन ने पाकिस्तानी तत्वों के जरिये शेख हसीना विरोधी आंदोलन को हवा दी। निश्चित ही शेख हसीना की छवि एक अधिनायकवादी शासक की बनी और पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका उनकी निंदा करने में मुखर हो उठा। अमेरिका उनकी नीतियों से पहले से ही खफा था, क्योंकि वह मानवाधिकार और लोकतंत्र पर उसकी नसीहत सुनने को तैयार नहीं थीं। उनका सत्ता से बाहर होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, बांग्लादेश में एक अर्से से भारत विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। उनका भारत विरोधी चेहरा आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान भी दिखा। यह ठीक नहीं कि हिंसक प्रदर्शनकारी अभी भी हिंदुओं और उनके मंदिरों के साथ भारतीय प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थितियां चीन और पाकिस्तान ने मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका में खड़ी की है।

हसीना का जाना या उनका निष्कासन चीन एवं पाकिस्तान की साजिशों का परिणाम है, जो भारत के लिए कई मायनों में झटका है। इसका यह मतलब भी है कि भारत ने पड़ोस में अपने इकलौते स्थिर साथी को अब खो दिया है। भारत अपने चारों ओर से बदहाल, कट्टरवादी, अराजक एवं अस्थिर पड़ोसियों से घिरा है। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, जिस पर कट्टरपंथी तालिबान का राज है। भारत-विरोधी समूहों को समर्थन देने का उसका एक काला इतिहास रहा है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश ही है। एक बेहद अशांत पड़ोस, जो कट्टरपंथियों, सैन्य शासकों, दिवालिया अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु-परिवर्तन के कारण डूबते देशों में अग्रणी है। अपनी आर्थिक बदहाली के बावजूद वह भारत विरोधी षडयंत्र रचता ही रहता है। वह राजनीतिक अस्थिरता का पर्याय है। विडम्बना देखिये कि पाकिस्तान के एक भी वजीरे-आजम ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। हमेशा वहां की फौज ने उनके कार्यकाल में टांग डाली है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका 2022 में दिवालिया हो गया था। वहां से सामने आई तस्वीरें एवं घटनाक्रम आज के बांग्लादेश से काफी मिलती-जुलती रही हैं। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बड़ा जनआंदोलन किया और जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिस कारण राष्ट्रपति गोटाबाया को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आर्थिक दिवालियेपन का शिकार यह देश चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। श्रीलंका के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चीन का था, जिस कारण चीन ने यहां के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया था। हालात यह हो गए थे कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था।

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं।

नेपाल बीते कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता के दौरे से गुजर रहा है। हाल ही में यहां एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रो-भारत माने जाने वाली प्रचंड सरकार सत्ता से बाहर हो गई। अब यहां चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की सरकार है। ओली इससे पहले 2015-16 में नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उस समय भारत और नेपाल के संबंध काफी तनावपूर्ण रहे थे। नेपाल में गत 16 वर्षों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं। हालात इतने बदहाल हैं कि वहां पर कुछ लोग राजशाही को फिर से बहाल करना चाहते हैं। नेपाल में भी चीन ने जाल बिछा रखा है। चीन विस्तारवादी, अलोकतांत्रिक और अपने आस-पड़ोस के देशों के साथ धौंस-डपट करने वाला देश है। वह भारत के भूखंडों पर अपनी मिल्कियत जताता रहता है। भूटान में घरेलू राजनीति स्थिर है, लेकिन वह चीन के साथ सीमा-समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता है, और यह भारत के लिए चिंता का बड़ा कारण है।

भारतीय उपमहाद्वीप के मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को दुनिया चुपचाप सब देख रही है, वहीं भारत इसके लिए खुद को तैयार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की घटनाओं का उस पर सीधा असर होगा। भारत शांति कायम रखने एवं पडोसी देशों से मित्रता कायम रखने के अपने संकल्पों एवं रणनीतियों के लिए इन देशों पर भरोसा नहीं कर सकता। हमारे इर्द-गिर्द मची उथलपुथल, अस्थिरता एवं अराजकता हमारे वैश्विक एजेंडे को भी बाधित करती है। भारत की आबादी 1.4 अरब है। उसके सभी पड़ोसियों की कुल आबादी 50 करोड़ है। अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही है। भारत की जीडीपी तीन ट्रिलियन डॉलर है। बाकी सब मिलाकर लगभग एक ट्रिलियन हैं। भारत समर्थ है, शक्ति सम्पन्न है, दुनिया की तीसरी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, इसलिये उसे अधिक बलों की तैनाती, अधिक रक्षा खर्च और सीमाओं पर अधिक बुनियादी ढांचों का निर्माण करना होगा। क्योंकि भारत के सभी पडोसी देशों पर चीन का दबदबा है और उसके दबाव में भारत के लिये कभी भी संकट बन सकते हैं।

बांग्लादेश के घटनाक्रम पर भारत की सतर्कता, विवेक एवं समझदारी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पडोसी देशों में उत्पन्न हालातों पर समझ एवं संयम से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तख्तापलट घटनाओं पर भी उसने पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी बात रखी। ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर सर्वसम्मति बनना जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पडोसी देशों में न मिलना ही उनकी अस्थिरता एवं अराजकता का बड़ा कारण है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी स्थिति कतई नहीं बननी चाहिए कि जहां राजनीतिक दलों के बीच दूरियां इस कदर बढ़ जायें कि फौज का दखल देना पड़े या पडोसी देश अपनी स्वार्थों की रोटियां सेंकने में सफल हो जाये। भारत के पडोसी देशों के लोग केवल बुराइयों से लड़ते नहीं रह सकते, वे व्यक्तिगत एवं सामूहिक, निश्चित सकारात्मक लक्ष्य के साथ जीना चाहते हैं। अन्यथा जीवन की सार्थकता नष्ट हो जाएगी।

इन पडोसी देशों के नेता दो तरह के हैं- एक वे जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे वे जो कुछ होना चाहते हैं। असली नेता को सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर, प्रासंगिक और अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनानी होती है। संयुक्त रूप से कार्य करें तो सभी पडोसी देश मिलकर विश्व में एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने सहचिन्तन को शायद कमजोरी मान रखा है। नेतृत्व के नीचे शून्य तो सदैव खतरनाक होता ही है पर यहां तो ऊपर-नीचे शून्य ही शून्य है। इन पडोसी देशों के स्तर पर तेजस्वी और खरे नेतृत्व का नितान्त अभाव है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के केनवास पर शांति, प्रेम, विकास और सह-अस्तित्व के रंग भरने की अपेक्षा है। भारत इस स्थिति में है, उसे मनोबल के साथ पडोसी देशों में स्थिरता, शांति, लोकतंत्र एवं आपसी समझ की ज्योत जलाने के लिये तत्पर रहना चाहिए, जो उन देशों के साथ भारत के लिये भी जरूरी है।

मालदीव एक समय भारत का सहयोगी हुआ करता था। वहां की अर्थव्यवस्था चीन और भारत पर निर्भर है। हालांकि, मालदीव की भारत से नजदीकी हमेशा चीन को खटकती थी, जिस कारण उसने इस देश को अपने कर्ज के जाल में फंसाया। धीरे-धीरे इस देश की माली हालत बुरी होने लगी, जिसके बाद यहां चीन समर्थक और इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू की सरकार बनी। पाकिस्तान एवं चीन के दबाव में उनके नए राष्ट्रपति के सुर बदले हुए हैं। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं। मुइज्जू ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले चीन का ही दौरा किया था और इसके बाद उन्होंने कई भारत विरोधी फैसले किए, जिसमें मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी भी शामिल थी। वहां भारत-विरोधी स्वर उग्रतम बने हुए हैं।

व्यापारियों ने चेक क्लियरिंग का समय घटाने के लिए आरबीआई के प्रस्ताव का किया स्वागत, कारोबार होगा सुगम

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) चेक समशोन में लगने वाले समय को कम करने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा करते हुए यह एलान किया। कारोबारियों ने केंद्रीय बैंक के इस फैसले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

भारतीय रिजर्व के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का एलान किया। इस दौरान उन्होंने चेक समाशोनधन प्रक्रिया को तेज करने से जुड़े प्रस्ताव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लाया गया है। इसके जरिए ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर कारोबारियों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि इससे कारोबार को काफी लाभ मिलेगा। हालांकि अब देश में कारोबारी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपना रहे हैंपर इसके बावजूद 25 से 30 प्रतिशत तक का कारोबार चेक के जरिए किया जाता है। ऐसे में आरबीआई के इस फैसले से कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।

25 से 30 प्रतिशत कारोबार चेक के जरिए होते हैं

कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का कहना है कि वर्तमान समय में क्रेडिट पर माल देना, कारोबारियों को सरकारी पेमेंट करना और व्यापार से जुड़े विशेषकर आयात-निर्यात से जुड़े कारोबारी चेक देते पेमेंट करते हैं। वर्तमान समय में 25 से 30 प्रतिशत कारोबार चेक पेमेंट से किया जाता है और यह करोड़ रुपये का होता है, चेक के जरिए 1000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रतिदिन होता है। सरकारी खरीदारी करने के लिए भी चेक से पेमेंट किया जाता है। इसलिए आरबीआई का यह फैसला राहत प्रदान करता है। इससे कुछ घंटों में चेक क्लियर होने से क्रेडिट पर दिए गए माल का पेमेंट मिल जाएगा। दूसरा चेक बाउंस की समस्या भी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। तीसरा बैंक जो दो से तीन दिन तक हमारे पैसों का इस्तेमाल करता था वह भी कम हो जाएगा।

चेक जल्दी क्लियर होने से कारोबार में होगी आसानी

भारत मर्चेंट चेंबर के राजीव सिंघल का कहना है कि बैंकों में चेक जमा करना और उसको क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लग जाता है। ऐसे में यदि किसी को माल खरीदना है तो माल तब ही मिलेगा जब उसका चेक क्लियर होगा। ऐसे में चार से पांच दिन चले जाते हैं। हालांकि ऑनलाइन पेमेंट की वजह से इस प्रकार समस्या अब नहीं आ रही

है। 80 प्रतिशत कारोबारी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। वे कहते हैं कि इसे लागू करने के बाद वर्तमान में हो रहे आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल थोड़ा कम होने की संभावनाएं बनती हैं। मुंबई में कालबादेवी के कपड़ा व्यापारी धर्मेश ठक्कर कहते हैं चेक क्लियरेंस कुछ ही घंटो में होने से कारोबार में आसानी तो होगी। बावजूद इसके ऑनलाइन पमेंट अधिक होता है, जो कि कारोबारियों के लिए सबसे फायदमेंद है। लेकिन चेक से भी लेनदेन कारोबारी करते हैं और इसका भी एक बड़ा हिस्सा कारोबार को प्रभावित करता है। इससे फैसले से कारोबार में तेजी आएगी और व्यापार बढ़ेगा।

ग्राहकों और कारोबारियों को होगी सुविधा

आरबीआई के इस फैसले से कारोबारियों और ग्राहकों दोनों को सुविधा मिलेगी। कारोबारी कहते हैं कि चेक जमा करने के बाद दो से तीन दिन तक इंतजार करना होता है, जो अब नहीं करना होगा। पहले की तुलना में बैंकों की छुट्टीयां अभी अधिक होने से चेक जमा होने के बाद भी छुट्टी होने की वजह से क्लियर नहीं होता है, कुछ घंटों में ही चेक क्लियर होने से यह समस्या भी नहीं रहेगी। चेक बाउसं होनी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि चेक देने से पहले चुकाने वाले को अपने एकाउंट में बैलेंस रखना जरूरी होगा। इसे लागू करने के बाद आरटीजीएस और एनईएफटी का इस्तेमाल थोड़ा कम होने की संभावना है।

नई व्यवस्था में क्या है प्रस्ताव?

आरबीआई के अनुसार नई व्यवस्था में चेक को स्कैन किया जाएगा। इससे कुछ ही घंटो में इसकी क्लियरिंग हो जाएगी। फिलहाल अभी चेक क्लियर होने में एक से दो दिन लगते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि इससे जुड़े दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों की तरफ से अपने ग्राहकों के बारे में क्रेडिट सूचना जो कि कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट अब हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव दिया है। इससे ग्राहकों को अपने सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर की जानकारी मिलती रहेगी।

सीसीडी से जुड़ी कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, यह है मामला

परिवहन विशेष न्यूज

एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की बेंगलुरु पीठ ने 8 अगस्त को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआईटीएसएल) की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कर्ज में डूबी कंपनी के संचालन की देखरेख के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया।

कॉरपोरेट विवाद न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है, यह कॉफी डे ग्रुप की मूल कंपनी है जो कैफे कॉफी डे नाम (सीसीडी) की कॉफी स्टोर्स की श्रृंखला का संचालन करती है। एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की बेंगलुरु पीठ ने 8 अगस्त को आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (आईडीबीआईटीएसएल) की ओर से दायर याचिका को स्वीकार कर लिया।

इस याचिका में सीडीईएल पर 228.45 करोड़ रुपये के भुगतान में चूकने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में एनसीएलटी ने कर्ज में डूबी कंपनी के संचालन की देखरेख के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर भी नियुक्त किया। सीडीईएल एक रिसॉर्ट का भी संचालन करती है। इसके साथ ही कंपनी परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी कॉफी बीन्स की बिक्री और खरीद का भी कारोबार करती है। कंपनी पर रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) के कूपन भुगतान के भुगतान में चूक का आरोप है। वित्तीय लेनदार ने निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 1,000 एनसीडी की सदस्यता ली थी और मार्च 2019 में सदस्यता के लिए 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस मामले में सीडीईएल ने आईडीबीआईटीएसएल के साथ एक समझौता किया था। आईडीबीआईटीएसएल डिबेंचर धारकों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त होने पर सहमत हुआ था। हालांकि, सीडीईएल सितंबर 2019 और जून 2020 के बीच विभिन्न तारीखों पर देय कुल कूपन भुगतान का भुगतान करने में चूक गई। नतीजतन, डिबेंचर ट्रस्टी ने सभी डिबेंचर धारकों की ओर से, 28 जुलाई, 2020 को सीडीईएल को डिफॉल्ट का नोटिस जारी किया और एनसीएलटी से संपर्क किया। सीडीईएल ने इस कदम का विरोध करते हुए दावा किया कि आईडीबीआईटीएसएल सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) शुरू करने के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी समझौता और डिबेंचर ट्रस्ट डीड सीआईआरपी शुरू करने के लिए उसे शक्तियां प्रदान नहीं करती हैं।

इंटेल के शेयरों में तबाही: 26 फीसदी गिरे चिपमेकर कंपनी के स्टॉक, निवेशकों के करोड़ों रुपये स्वाहा

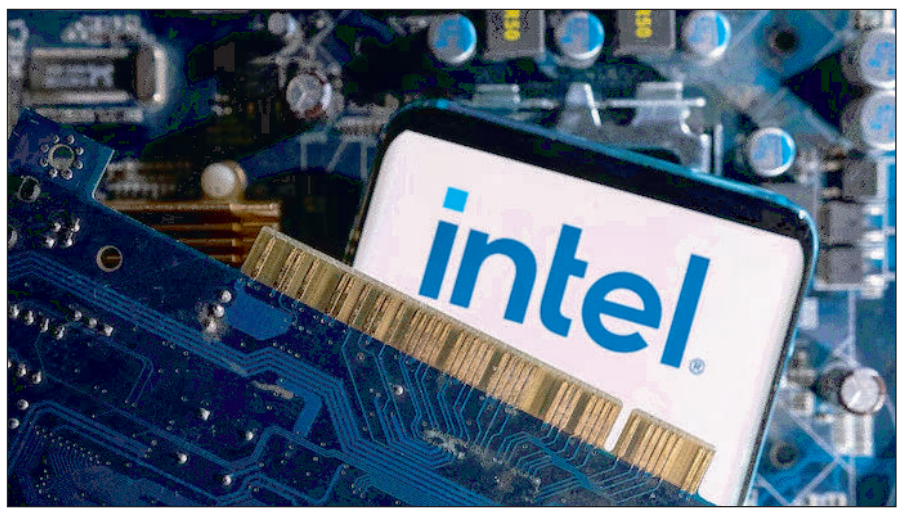

अमेरिकी शेयर बाजार में शुक्रवार को इंटेल के स्टॉक 26 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। यह पिछले पांच दशक में इंटेल के शेयरों का सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में इंटेल के स्टॉक ने एक दिन में 31 फीसदी का गोता लगाया था। उस वक्त कंपनी को लिस्ट हुए सिर्फ 3 ही साल हुए थे। इंटेल के तीसरी तिमाही के नतीजे हद से ज्यादा खराब रहे थे।

नई दिल्ली। अमेरिकी चिप निर्माता इंटेल (Intel) ने कई सालों तक मार्केट में एकछत्र राज किया। लेकिन, अब कंपनी शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एनवीडिया और क्वालकॉम जैसे प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। कंपनी एआई प्रोसेसर के मामले में भी कोई बड़ी तरक्की नहीं कर पा रही। उसके दूसरी तिमाही के नतीजे भी बेहद निराशाजनक रहे।

इंटेल के शेयरों का बुरा हाल

इन सबका असर इंटेल के शेयरों पर भी दिखा। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में इंटेल के स्टॉक 26 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए। यह पिछले पांच दशक में इंटेल के शेयरों का सबसे खराब प्रदर्शन है। इससे पहले 1974 में इंटेल के स्टॉक ने एक दिन में 31 फीसदी का गोता लगाया था। उस वक्त कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए सिर्फ 3 ही साल हुए थे।

10 के निचले स्तर पर इंटेल

शुक्रवार को इंटेल के स्टॉक (Intel Share Price) 26.06 फीसदी टूटकर 21.48 डॉलर (1,799 रुपये) पर आ गई। यह पिछले एक दशक में कंपनी के शेयरों का सबसे निचला स्तर है। टूट गई और इसके शेयर 10 साल (2013 के बाद) के निचले स्तर पर पहुंच गए। इंटेल के शेयरों ने पिछले 6 महीने में करीब 50 फीसदी और पांच साल में 55 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इससे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ है।

छंटनी करने का भी एलान

इंटेल को तीसरी तिमाही में 1.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। कंपनी ने घाटा और कामकाजी खर्च करने के लिए करीब 18 हजार कर्मचारियों की छंटनी करने का फैसला किया है। उसने चौथी तिमाही के लिए निवेशकों को दिए जाने वाले डिविडेंड को भी निरस्त कर दिया। कंपनी अपने खर्चों में कुल 20 अरब डॉलर की कमी लाने की योजना बना रही है।

हिंडनबर्ग का आरोप- सेबी चीफ का अदाणी की कंपनियों में निवेश, पति धवल के साथ मिलकर लगाए पैसे

SEBI: अमेरिका की रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपने नई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का नाम कथित अदाणी घोटाले में जुड़ा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों की अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी की ओर से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आयी है।

अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार नियामक सेबी की प्रमुख और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ताजा रिपोर्ट सामने आने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के नाम कथित अदाणी घोटाले से जुड़ रहा है। शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कथित अदाणी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में दंपती की हिस्सेदारी थी।

हिंडनबर्ग ने अरबपति उद्योगपति गौतम अदाणी के कारोबारी समूह से जुड़ी अपनी पिछली रिपोर्ट के 18 महीने बाद एक नया ब्लॉगपोस्ट रिलीज किया। इसमें आरोप लगाया गया है कि सेबी ने अदाणी के मॉरीशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कथित अघोषित जाल में आश्चर्यजनक रूप से रुचि नहीं दिखाई है। अमेरिकन शॉर्ट-सेलर ने 'व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों' का हवाला देते हुए दावा किया, 'सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति के पास अदाणी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी।'

हिंडनबर्ग बोला- 18 महीने से मौन है सेबी; जून 2024 में भेजा कारण बताओ नोटिस

नई रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा, अदाणी समूह पर हमारी मूल रिपोर्ट को लगभग 18 महीने बीत चुके हैं। इस बात के पर्याप्त सबूत पेश किए जा चुके हैं कि भारतीय कारोबारी समूह (अदाणी) कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाले में संलिप्त रहा है। हालांकि, ठोस सबूतों और 40 से अधिक स्वतंत्र मीडिया जांच के बावजूद सेबी ने अदाणी समूह के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के बजाय जून, 2024 में सेबी ने हमें एक स्पष्ट 'कारण बताओ' नोटिस भेजा।

सेबी की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं

मॉरीशस में अदाणी ग्रुप के काले धन नेटवर्क की पूरी जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अदाणी घोटाले में इस्तेमाल की गई अपतटीय (ऑफशोर) संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति की हिस्सेदारी थी। इन संस्थाओं का संचालन कथित तौर पर अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी के बड़े भाई विनोद अदाणी करते हैं। हालांकि सेबी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

माधबी पुरी बुच ने पति को ट्रांसफर किए अपने शेयर

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि माधवी पुरी बुच ने अपने शेयर पति को ट्रांसफर किए। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवी पुरी बुच सेबी की सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन थीं। उनका सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसलटिंग फर्म में 100 फीसदी स्टेक था। 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से दो हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए।

पिछले साल अदाणी समूह को लगा था झटका

बता दें कि पिछले साल ही यह कंपनी एक रिपोर्ट के जरिए अदाणी समूह को तगड़ा झटका दे चुकी है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदाणी समूह पर निशाना साधते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अदाणी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जारी होने के बाद शेयर बाजार में भूचाल आ गया था। निवेशकों के करोड़ों रुपये डूबे थे। अदाणी समूह के अधिकांश शेयरों में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट आने से पहले गौतम अदाणी दुनिया के धनकुबेरों में नंबर दो अरबपति थे, लेकिन नकारात्मक खबरों के कारण वे 36वें नंबर पर खिसक गए थे।

क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च?

हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी का काम इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स का विश्लेषण करना है। यह किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है। इसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी की रिपोर्ट प्रकाशित करती है।

'एथनॉल उत्पादन के लिए चीनी मिलें गन्ने का विकल्प तलाशें', बोले- सहकारिता मंत्री अमित शाह

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ (एनएफसीएसएफ) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने शनिवार को कहा, बीस प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 रखा गया है। हम 2025-26 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चीनी मिलों से एथनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के अलावे अन्य विकल्प तलाशने का आह्वान किया है। उन्होंने इस दौरान जैव ईंधन विनिर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ (एनएफसीएसएफ) की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने शनिवार को कहा, बीस प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 रखा गया है। हम 2025-26 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा, सरकार के एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम से देश के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है।

शाह ने चीनी मिलों के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा,

₹आपको भविष्य को देखते हुए अवसरों को पहचानने और संभावनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। एथनॉल का निर्माण कई स्रोतों से बनाया जा सकता है। विविधीकरण के लिए यह प्रयास ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना चाहता है।"

वित्त मंत्री बोलीं- बांग्लादेश संकट से कपड़ा उद्योग अनिश्चितता में, जल्द बदल सकते हैं हालात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बांग्लादेश का माहौल तनावपूर्ण होने से वहां कपड़ा और सिले हुए वस्त्र उद्योग में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में किया गया सारा निवेश सुरक्षित है।

भारत का कपड़ा उद्योग बांग्लादेश संकट के कारण थोड़ी अनिश्चितता का सामना कर रहा है, पर जल्द ही हालात सामान्य होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात शनिवार को बजट के बाद होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की निदेशक मंडल की बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार से जल्द ही चुनौतियों का समाधान करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सीमा सुरक्षित रहे इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। बांग्लादेश में भारत के निवेश पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का कपड़ा उद्योग विशेषकर तमिलनाडु से बांग्लादेश में विश्वास के आधार पर निवेश किया गया है और उन्होंने वहां अच्छा काम किया है। श्रम और आरक्षण में नरमी की नीति जैसा कि कम आय वाले देशों में होता है के कारण वहां के कपड़ा उद्योग का निर्यात भी बढ़ा है। वहां काम कर रहे भारतीय कपड़ा उद्योगों की ओर से भारत को भी निर्यात किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश का माहौल तनावपूर्ण होने से कपड़ा और सिले हुए वस्त्र उद्योग में थोड़ी अनिश्चितता का माहौल है। वित्त मंत्री ने कहा, ₹मुझे उम्मीद है कि वहां (बांग्लादेश में) किया गया सारा निवेश सुरक्षित है। अभी यह कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी कि पड़ोसी देश में जो हालात बने हैं उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?"

वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि जल्द ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मुद्दों को सुलझाएगी और दोनों देशों (भारत और बांग्लादेश) के लोगों के लिए स्थिति सामान्य हो जाएगी।

बीते हफ्ते बांग्लादेश में उस समय राजनीतिक संकट गहरा गया जब आरक्षण के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत पहुंच गईं। उसके तुरंत बाद वहां संसद को भंग कर दिया गया और सेना के समर्थन से अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसकी कमान पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई। उन्होंने गुरुवार को शपथ ली और शुक्रवार को अपने 16 सदस्यीय सलाहकार मंडल के बीच विभागों का बंटवारा किया।

बांग्लादेश के बड़े नेता ने खोल दी प्रदर्शन की पोल

बोले- हिंदुओं पर हो रहे हमले, कुछ लोग उठा रहे फायदा

बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही है। अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद अब प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन वहां के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को भी अल्टीमेटम दे दिया जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। हिंदुओं के खिलाफ वहां हिंसा अब भी जारी है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। पड़ोसी मुल्क में शेख हसीना (Sheikh hasina) को सत्ता से बेदखल करने के बाद अंतरिम सरकार का गठन भी हो चुका है।

इसके बावजूद हिंसा का आलम ये है कि बीते दिन वहां के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन को भीड़ ने अल्टीमेटम दे दिया, जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा।

चुनाव पर फैसला नहीं

बांग्लादेश में अभी ये साफ नहीं हुआ है कि वहां चुनाव कब होंगे, लेकिन यह तय है कि देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) इनमें अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्य न्यायाधीश के फैसलों से नाराज थे लोग

टीवी चैनल एनडीटीवी को दिए एक इंटव्यू में बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश (Bangladesh Chief Justice) को अपना पद छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के कारण छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश शेख हसीना सरकार के निकट माने जाते थे और कहा जाता था कि वो उनके पक्ष में ही फैसले देते हैं।

कुछ लोगों ने हिंदुओं को निशाना बनाया

बीएनपी नेता ने कहा कि देश में हिंदुओं पर हमले कुछ लोगों द्वारा स्थिति का लाभ उठाने का परिणाम हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे किसी स्व्यवस्थित एजेंडेस का हिस्सा नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जब किसी भी देश में कोई बदलाव होता है, तो कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।

बांग्लादेश में भी दुर्भाग्य से हर क्रांति के साथ, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जाता है, चाहे वे मुस्लिम हों या हिंदू। उन्होंने माना कि अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक या व्यवस्थित एजेंडा नहीं बताया।

भारत-बांग्लादेश संबंध होंगे बेहतर

आलमगीर ने आगे कहा कि यदि जिया पर्याप्त रूप से योग्य होंगी तो वे चुनावों में बीएनपी का नेतृत्व करेंगी और यदि पार्टी सत्ता में आती है तो भारत-बांग्लादेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी।

शेख हसीना बंग्लादेश वापसी को है तैयार, पर शर्त है

परिवहन विशेष।एसडी सेठी। बंग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद भारत की शरण में आ गई है। वह 5 अगस्त को भारत भाग कर आई। अब हसीना से जुडी साहसिक बडी खबर आ रही है।बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने खुलासा किया है कि जैसे ही वहां नई कार्यवाहक सरकार चुनाव कराने का फैसला करेगी, वह अपने देश वापस लौट आएगी। बांग्लादेश में नोबल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने 8 अगस्त को शपथ ले ली है।अब वहां चुनाव कराने का काम सौपा जाएगा। लेकिन इस बीचं स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश की सुप्रीमकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया है।पता चला है कि सीजेआई बांग्लादेश ने इस्तीफा दे दिया है। यानि अराजकता अभी थमी नही है। वहीं शेख हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने खुलासा किया है कि फिलहाल शेख हसीना भारत में है। अंतरिम सरकार द्वारा चुनाव कराने का फैसला किए जाने के तुरंत बाद वे बांग्लादेश वापस चली जाएगी। दरअसल, शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी अंतरिम सरकार में शामिल नहीं है। क्योंकि लंबे समय तक पूर्व प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के- .खिलाफ छात्रो के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। जिन्होने देशव्यापी हिंसा के.बाद पद छोडा था। जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। अब सवाल उठता है कि क्या हसीना की अवामी लीग चुनाव लाएगी? इस पर बेटे वाजिद जॉय ने खुलासा किया कि अगर जरूरत पडी तो वह राजनीति में शामिल होने से परहेज नहीं करेगें। उन्होने साफ किया कि मुझे यकीन है कि अवामी लीग चुनाव में हिस्सा लेगी।और हम जीत भी सकते है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना इस वक्त नई दिल्ली में एक सुरक्षित घर में शरण लिए हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वह ब्रिटेन में शरण लेने की योजना बना रही है।लेकिन ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक उन्होने बांग्लादेश के बारे में अपने ब्रिटिश समकक्ष से बात की लेकिन उन्होने कोई खुलासा नही किया।

मुझसे सलाह लेने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सभी इसकी अनदेखी कर रहे हैं : गोबर्धन पीठ शकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती

मनोरंजन सासमल , स्टेटे हेड उडीशा

भुबनेस्वर : ओडिशा में भाजपा के सत्ता में आने के बाद श्रीमंदिर के चारद्वार को भक्तों के प्रवेश के लिए खोल दिया गया। कई वर्षों के बाद भी महाप्रभु के आभूषण खुले हैं। राज्य सरकार ने इस मुद्दे या मंदिर के किसी अन्य मुद्दे पर उनकी सलाह नहीं ली है । गोबर्धन पीठ शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि वे मंदिर के किसी भी मामले में मुझसे नहीं पूछ रहे हैं और न ही सलाह ले रहे हैं ।शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयसेबक संघ के नेता मोहन भगत ने गोवर्धन पीठ में शंकराचार्य से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, मातृशक्ति की रक्षा जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई । इस मौके पर जगतगुरु ने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं । राज्य सरकार किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मामले में मेरी सलाह नहीं ले रही है । गजपति के महाराजा, मंदिर की प्रबंधन समिति, सरकार सभी मुझसे दूरी बना रहे हैं। श्रीमंदिर के मुद्दे पर सरकार शंकराचार्य की राय नहीं ले रही है । जब महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, चाहे वह रत्नों के बारे में हो या किसी अन्य मामले में, मुझे सूचित नहीं किया जाता ।हालांकि मंदिर के किसी भी काम में मुझसे सलाह लेने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सभी इसकी अनदेखी कर रहे हैं । महाप्रभु के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में राजनेता निर्णय ले रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है । ऐसे मनमाने काम से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बढ़ठाकुर बलभद्र रथ में गिर पड़े। शंकराचार्य ने कहा कि महाप्रभु सब कुछ सह लेंगे, घमंड नहीं करेंगे, आगे बड़ा खतरा आ रहा है ।

बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार, हिंसा के खिलाफ ढाका से US तक प्रदर्शन; एक्शन मोड में भारत सरकार

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने की नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश की राजधानी ढाका और दुनिया के दूसरे देशों में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को बचाया जाए के नारे भी लगाए।

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं थमने की नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश की राजधानी ढाका और दुनिया के दूसरे देशों में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया।

ढाका में हिंदुओं का बड़ा प्रदर्शन

बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति के चलते हिंदुओं को अभी तक निशाना बनाया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। इसी हिंसा के खिलाफ बीते दिन ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। पड़ोसी मुल्क में हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया जा रहा है।

लंदन से अमेरिका तक विरोध प्रदर्शन

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और अन्य लोगों को निशाना बनाकर की गई कथित हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और बांग्लादेशी झंडे लिए हुए थे और पोस्टर पकड़े हुए थे, जिसमें मांग की गई थी कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को स्बचाया जाए।स उन्होंने 'हमें न्याय चाहिए' के नारे लगाए और हाल ही में हिंसा में वृद्धि के बीच शांति का आह्वान किया।

वहीं, लंदन और फिनलैंड सहित दुनिया के कई और हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन की खबरें आईं।

एक्शन में मोदी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की अपील की। भारत सरकार के अधिकारियों का कहना है कि वो इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अंतरिम सरकार से लगातार संपर्क में हैं।

पीएम मोदी देश के किसानों को देंगे खास तोहफा, आज 61 फसलों की 109 किस्में करेंगे जारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज देश के किसानों को खास तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की फोर्टिफाइड अधिक उपज देने वाली जलवायु अनुकूल 109 किस्में जारी करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान किसानों और विज्ञानियों से बातचीत भी करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहते हैं।

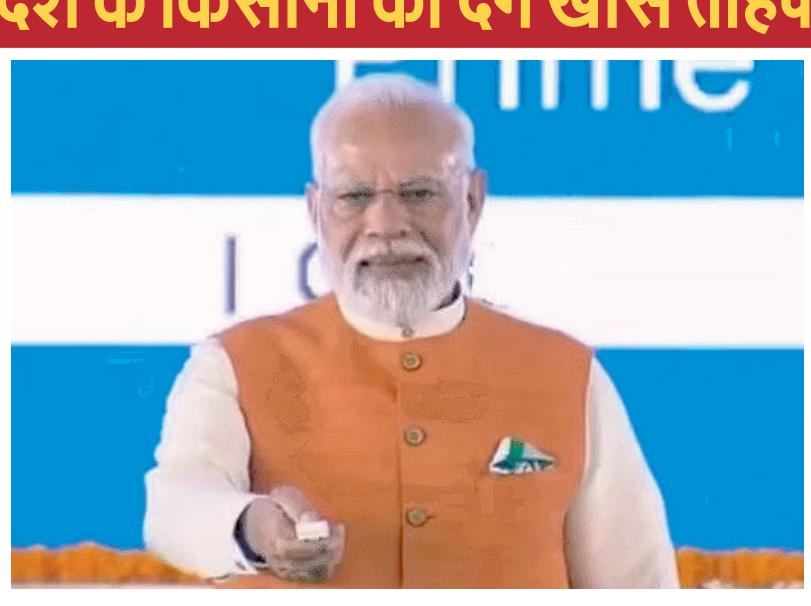

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 61 फसलों की फोर्टिफाइड, अधिक उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल 109 किस्में जारी करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान किसानों और विज्ञानियों से बातचीत भी करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पौधों की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहते हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को बताया कि 61 फसलों की 109 किस्मों में खेत में उगाई जाने वाली 34 फसलें और 27 बागवानी फसलें हैं। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलें शामिल हैं। बागवानी फसलों में फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में जारी की जाएंगी।

उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे

पीएम मोदी ने हमेशा से टिकाऊ खेती और जलवायु अनुकूल पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए फसलों की फोर्टिफाइड किस्मों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया है। इन कदमों से किसानों की अच्छी आय सुनिश्चित होगी और उनके लिए उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे।

खेतों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने पर जोर

109 उच्च उपज वाली किस्मों को जारी करने का यह कदम इस दिशा में एक और कदम है। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम (पीएम प्रमोशन आफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन फार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट) योजना को शुरू की है।

सैकड़ों जवानों की तैनाती, 71 घंटे में पुल तैयार; वायनाड भूस्खलन के बाद जब एक्शन में आई मोदी सरकार

वायनाड में भूस्खलन से आई त्रासदी के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए राज्य को मदद पहुंचाई थी। सरकार ने सेना एनडीआरएफ समेत विभिन्न दलों के 1200 से अधिक जवान तैनात किए थे। साथ ही 100 से अधिक एंबुलेंस भी भेजी गई थीं। सेना ने 71 घंटो में पुल बनाया था जिससे 200 लोगों की जान बच सकी थी।

नई दिल्ली। केरल के वायनाड में भूस्खलन की त्रासदी के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना, वायु सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवाओं और सिविल डिफेंस सहित अन्य विभागों के 1,200 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया था। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि चिकित्सा सहायता और उपचार के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक एंबुलेंस तैनात की गईं। भारतीय सेना ने वायनाड में 190 फुट लंबा बेली ब्रिज (अस्थायी पुल) बनाया, जिससे प्रभावित स्थलों तक भारी साजो सामान और एंबुलेंस की आवाजाही सुनिश्चित हो सकी और राहत और बचाव कार्य में तेजी आई।

पुल से 200 लोगों की बचाई गई जान

इसके चलते पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण फंसे लगभग 200 लोगों को बचाने के लिए काम किया जा सका। यह पुल 71 घंटे में बनकर तैयार हो गया। उन्होंने बताया कि अब तक 520 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एनडीआरएफ की बचाव टीमों द्वारा 112 शव बरामद किए गए हैं। इस साल केरल एसडीआरएफ के खाते में एक अप्रैल को लगभग 395 करोड़ रुपये थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023